वर्ष-11, अंक-8, मई-2026

मूल्य: ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

'कर्मयोगी' सुशासन और विकास के दो स्तंभ

विक्रमादित्य सिंह मलिक (IAS)
नगर आयुक्त, गाजियाबाद

ज्ञानेंद सिंह (IAS)
जिलाधिकारी, पीलीभीत

गाजियाबाद की 'वैश्विक पहचान' और पीलीभीत की 'बुनियादी क्रांति' के शिल्पकार

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शक्ति से समृद्धि

नारी
उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी

नवनिर्माण के 9 वर्ष

सुरक्षा से समझौता नहीं
सभी थानों में 'मिशन शक्ति' केंद्र

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
26.81 लाख+
बेटियां सशक्त

निराश्रित महिलाओं को पेंशन

लखपति दीदी योजना
18.55 लाख+
महिलाएं बनीं लखपति

महिला श्रम बल भागीदारी
13% से बढ़कर 36%

1 करोड़+
ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

मेधावी छात्राओं को स्कूटी का उपहार

कामकाजी महिलाओं के लिए
श्रमजीवी महिला छात्रावास

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड
ब्याज मुक्त ऋण

10,400+
स्टार्ट-अप का नेतृत्व

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

अन्दर के पेजों में...

वर्ष- 11 अंक- 8

मई-2026

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक

अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा

संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक

स्व. वेद प्रकाश शर्मा

अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी

अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,

प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार

विजय अरोड़ा, राहुल अग्रवाल,

सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी

डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड

रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार

कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)

वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)

अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

सम्पादक - ललित कुमार शर्मा

RNI No. UPHIN/2015/61611

ई-मेल: winews.in@gmail.com

वेबसाइट: www.winews.in

सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

कवर स्टोरी पेज-28

पीएम मोदी का भाषण देश की जनता के लिए गंभीर चेतावनी — पेज 03

पांच विधानसभा चुनाव: बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार — पेज 07

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे तय किया संन्यासी से मुख्यमंत्री तक का सफर? — पेज 14

नीट पेपर लीक, परीक्षा निरस्तीकरण और युवाओं के भविष्य पर सियासी संग्राम तेज — पेज 18

सामंथा रुथ: मॉडलिंग से टॉप एक्ट्रेस बनने तक, उतार-चढ़ाव भरा रहा फिल्मी सफर — पेज 52

स्टार एथलीट नीरज चौपड़ा और मनू भास्कर विदेश में करेंगे स्पेशल ट्रेनिंग — पेज 54

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

2026 में भारत के सामने बढ़ सकती हैं आर्थिक चुनौतिया

ललित कुमार
सम्पादक

इसमें कोई दोराय नहीं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद जिस स्तर पर वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई, उसका प्रभाव दुनिया के ज्यादातर देशों पर पड़ा है। भारत में भी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से कई स्तर पर झटके लगे हैं, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक संरचना पर पड़ा है। इसके बावजूद भारत ने अपने स्तर पर हालात से निपटने की कोशिश की है और यही वजह है कि आने वाले दिनों की चुनौतियों के समांतर कुछ सकारात्मक संकेत अब भी कायम हैं। वैश्विक स्तर पर ज्यादातर देशों को लगे आर्थिक झटकों के असर का दायरा अब भी फैल रहा है और शायद संयुक्त राष्ट्र की ओर से इन्हीं वजहों से भारत की विकास दर प्रभावित होने की आशंका जाहिर की गई है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की ओर से विगत दिनों जारी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती कर दी गई है। इसके मुताबिक, वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.6 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत हो सकती है। निश्चित तौर पर यह भारत के लिए एक चुनौती भरा वक्त साबित हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जिस तरह विकास दर में इस अनुमानित संशोधन के बावजूद भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बने रहने का आकलन पेश किया है, उससे एक उम्मीद भी पैदा होती है। दरअसल, पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद जैसी स्थितियां पैदा हुई, उसका असर इस रूप में आने की आशंका पहले से जताई जा रही थी। सच यह है कि न केवल भारत, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अप्रत्याशित साबित हो रहे संकट का दायरा और भी विस्तृत हो सकता है, क्योंकि 2026 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान भी महज 2.5 प्रतिशत आंका गया है। यह छिपा नहीं है कि दुनिया के ज्यादातर प्रभावित देशों में इसकी वजह से विकास की रफ्तार धीमी हुई है और सभी जगहों पर महंगाई का दबाव तेजी से बढ़ा है। आम लोगों की क्रयशक्ति कमजोर होने का सीधा असर बाजार पर पड़ता है और उसका सिरा आगे उत्पादन क्षेत्र तक भी जाता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए नीति-निर्माण के मामले में विकल्प कम होते जाते हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उछाल और व्यापारिक अनिश्चितता का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत समेत कई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। खासतौर पर ईरान और अमेरिका-इजराइल युद्ध से उपजे हालात में तेल आयात पर निर्भर countries की चिंताएं बढ़ी हैं। सच यह है कि जिस तरह ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया, उसकी वजह से अन्य देशों के साथ-साथ भारत को भी इसका बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा है। यों भारत ने इसका विकल्प निकालने की कोशिश की है और तेल आयात के लिए अन्य कुछ देशों के साथ कूटनीतिक संवाद कायम किया है, लेकिन फिलहाल बाधित आपूर्ति श्रृंखला की वजह से अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में ऊर्जा आयात के क्षेत्र में बढ़ती लागत और वित्तीय स्थितियों पर लगातार बढ़ते दबाव की वजह से अगर भारत की विकास दर भी चुनौतियों के बीच है, तो यह एक स्वाभाविक स्थिति है। मगर इसका सामना करना इस बात पर निर्भर है कि सरकार नए विकल्पों को लेकर कितनी स्पष्ट है और कितनी इच्छाशक्ति के साथ पहल करती है। भू-राजनीतिक उथल-पुथल और पश्चिम एशिया में युद्ध से उपजे संकट के बीच भारत को भी कई तरह की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में वैश्विक एजेंसियों की अलग-अलग रिपोर्ट में भारत की विकास दर में कमी आने के संकेत सामने आ रहे हैं। अब देश में बढ़ती महंगाई से यह चुनौती और बड़ी होती दिख रही है। हाल ही में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपए की वृद्धि, खुदरा और थोक महंगाई दर के बढ़कर क्रमशः 3.48 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत हो जाने, निर्यात में कमी और आयात लागत में उछाल जैसे कारणों से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की ओर जारी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती कर दी गई है। इसके मुताबिक, वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.6 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत हो सकती है। निश्चित तौर पर यह भारत के लिए एक चुनौती भरा वक्त साबित हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जिस तरह विकास दर में इस अनुमानित संशोधन के बावजूद भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बने रहने का आकलन पेश किया है, उससे एक उम्मीद भी पैदा होती है।

पीएम मोदी का भाषण देश की जनता के लिए गंभीर चेतावनी

कोरोना काल की तरह एक बार फिर से जनता पर लगाई जाएंगी पाबंदियां

इंद्रेश शर्मा

अमेरिका और ईरान के युद्ध के चलते पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है। अब इसका असर भारत पर भी बहुत गहरा पड़ने वाला है। मध्य पूर्व एशिया में चल रहे युद्ध के संकट को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने 24 घंटों में दो बार देशवासियों को इसके संकेत भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने डीजल, पेट्रोल का प्रयोग कम से कम करने, स्वदेशी अपनाने और सोने की खरीद बंद करने की अपील की है। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि भारत का पैसा भारत में ही रहना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा। इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से देश में कोरोना काल जैसे हालात होने का भी जिक्र किया। साफ है, आर्थिक व्यवस्थाएं दरक रही हैं।

बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद देश के प्रधानमंत्री को देश के हालात और देशवासियों का ध्यान आया। जब ध्यान आया तो समझ में आया कि हालात कोरोना काल की तरह से एक बार फिर हाथ से निकल रहे हैं। लिहाजा देशवासियों को ही इसे संभालने के लिए कह देना चाहिए। जनता को बता देना चाहिए कि हालात सरकार के बस से बाहर हो चुके हैं और अब कोरोना काल की तरह संकट की इस गेंद को जनता के ही पाले में डाल देना चाहिए। पीएम मोदी के भाषण के चंद घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को ₹पूरी तरह अस्वीकार्य₹ बताया है, जो ईरान ने युद्ध खत्म करने के मकसद से भेजा था। यानी फिलहाल ईरान युद्ध को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है जो ग्लोबल इकोनॉमी (भारत समेत) और शेयर बाजार के लिए भी अच्छी खबर नहीं है।

पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत के लोगों से पेट्रोल और डीजल को लेकर किफायत बरतने को कहा है। साथ ही एक साल तक सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील की और इस दौरान लोगों से विदेश यात्रा टालने की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पीएम के इस भाषण को शेयर करते हुए उनकी अपील को दोहराया। कुछ विशेषज्ञों ने पीएम के भाषण को डीकोड करते हुए भारत को मुश्किल दिनों से तैयार रहने के लिए कहा तो वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि ईरान वॉर से पैदा हुए हालात को सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है और इस मुश्किल को हैंडल करने की ज़िम्मेदारी जनता के कंधों पर डाल रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग पीएम के बयान से सहमति जता रहे हैं तो वहीं कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान इस संकट को देशवासियों से क्यों छुपाया गया। आइए समझते हैं कि पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा और उसके मायने क्या हैं। और अपने इस बयान को लेकर वो विपक्ष के निशाने पर क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए लोगों से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़े-बड़े तेल के कुएं नहीं हैं। हमें अपनी जरूरत के पेट्रोल-डीजल-गैस ये

सभी बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। आसमान को भी पार कर गए हैं। पड़ोस के देशों में क्या है वो तो अखबारों में आता है। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) में जहाजों की आवाजाही लंबे समय से प्रभावित है।

ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया भर की तेल सप्लाई का 20 फीसदी हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। भारत भी अपनी तेल और ऊर्जा जरूरतों के लिए होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली सप्लाई पर काफी हद तक निर्भर है। ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बड़ी मात्रा में तेल आयात करना पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पीएम ने इसी वजह से पेट्रोल और डीजल को लेकर संयम से काम लेने को कहा है क्योंकि युद्ध के कारण कच्चे तेल के साथ-साथ, खाने के तेल, फर्टिलाइजर और लिक्विड नेचुरल गैस (एलएनजी) गैस के दाम भी बढ़ने की आशंका है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम और विमान यात्रा भी महंगी हो सकती है। पीएम का भाषण संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संकट के असर को लेकर दिए गए उनके दो बयानों के बाद आया है।

यह साफ इशारा करता है कि अब ज्यादा समय तक सब कुछ सामान्य तरीके से नहीं चल सकता और सप्लाई चेन से जुड़ी परेशानियां आने वाली हैं। भारत, तैयार हो जाओ, आगे का सफर मुश्किल और झटकों भरा हो सकता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 भारत ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात पर 144 बिलियन डॉलर खर्च किए। विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि पीएम का बयान भारत के लिए एक चेतावनी जैसी है, क्योंकि अगर होर्मुज की नाकाबंदी लंबे वक्त तक जारी रहती है, अगर कच्चे तेल की कीमत 110 या 120 डॉलर प्रति बैरल पर बनी रहती है तो महंगाई बढ़ेगी। वित्तीय घाटा बढ़ेगा और कुल मिलाकर इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

सोना नहीं खरीदने के संदेश में गहरा राज

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 51.4 बिलियन डॉलर था। 2023 में यह 45.54 बिलियन डॉलर था। यानी 2024-25 में यह 13.7 फीसदी बढ़ गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी फॉरेक्स) 9 मई 2026 तक लगभग 690.6 अरब डॉलर था। पीएम मोदी की एक साल तक सोना मत खरीदिए वाली अपील अपने भीतर एक बड़ा संदेश छिपाए हुए है, रुपये को बचाइए। यह विदेशी मुद्रा संकट से निपटने की शुरूआती चेतावनी जैसी लगती है, क्योंकि आयातित सोने पर खर्च होने वाला हर अतिरिक्त डॉलर रुपये को और कमजोर करता है। भारत में सोने की भारी मांग है। देश हर साल लगभग 800-900 टन सोना आयात करता है, जो दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्तर पर है। कच्चे तेल के बाद सोना भारत का सबसे बड़ा आयात है. वित्तीय वर्ष 2026 में सोने का आयात रिकॉर्ड लगभग 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2025 के लगभग 24% ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक सोने को लेकर दिया गया पीएम मोदी का बयान बताता है कि सरकार डॉलर रिजर्व को बचा कर रखने पर जोर दे रही है। साथ ही नॉन एसेंशियल इंपोर्ट (गैर जरूरी आयात) को कम करना चाहती है और ईरान युद्ध से पैदा हुए दीर्घकालीन दबाव के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहती है।

सोना ना खरीदने को क्यों कहा ?

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। एक समय था जब संकट आता था तब लोग देशहित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है लेकिन, देशहित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ₹सोना नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें यह स्वीकार करके विदेशी मुद्रा बचानी होगी। कच्चे तेल और सोना दोनों को ही भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है। ऐसे में इन्हें खरीदने के लिए और ज्यादा विदेशी मुद्रा (आम तौर पर डॉलर) की जरूरत पड़ेगी और जिसकी वजह से रुपया कमजोर होगा और ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेगा, इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा भंडार) जब कम होता है तो सरकार की चिंता दो स्तरों पर होती है। कच्चे तेल के आयात को लेकर और सोने के आयात को लेकर। विशेषज्ञों के मुताबिक इसी वजह से पीएम ने अपने भाषण में कच्चे तेल के साथ-साथ सोना ना खरीदने की भी सलाह दी है।

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम की अपील उनकी नाकामी का सबूत है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस भाषण के बाद कहा कि ये नाकामी का सबूत है, अब जनता को यह बताना पड़ रहा कि क्या खरीदें और क्या नहीं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं।

उन्होंने लिखा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है- क्या खरीदें, क्या न खरीदें, कहां जाएं, कहां न जाएं।हर बार ज़िम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष से निपटने में नीतिगत विफलता के बाद अब चुनावी फैसलों का बोझ नागरिकों पर नहीं डाला जा सकता और उनसे तेल बचाने, यात्रा कम करने या खरीदारी घटाने की अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने सरकार को समझाइश देते हुए कहा कि मंत्रियों और नेताओं के लंबे चौड़े मोटर काफिलों पर रोक लगाकर, बड़ी-बड़ी रैलियों को एक साल के लिए बंद करके और भव्य शपथ ग्रहण समारोहों को बंद करके, उन्हें वॉच फ्रॉम होम (घर से देखकर) भी पेट्रोल और डीजल बचाया जा सकता है। चुनाव खत्म हो गए हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन की बचत करने को कहा है और विदेश यात्रा पर ना जाने की सलाह दी है। वो शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और इटली के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा कि वैश्विक संकट के इस दौर में मोदी जी ने देशवासियों से एक दूरदर्शी अपील की है। पेट्रोल-डीजल के उपयोग में संयम, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का उनका यह आह्वान भारत को

आत्मनिर्भर और एनर्जी-सिक्योर राष्ट्र बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। यह वैश्विक चुनौतियों के बीच देश को एक स्थिर, सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक सिद्ध होगा। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तेल और गैस को लेकर की गई अपील पर देशवासी अमल करें।

चुनाव खत्म होते ही 'संकट' याद आ गया: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए सोमवार को कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को 'संकट' याद आ गया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा संकट भाजपा ही है और केंद्र सरकार की हालिया अपीलें उसकी आर्थिक व नीतिगत विफलताओं को उजागर करती हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि यदि इतनी पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं तो पांच ट्रिलियन डॉलर की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के हाथ से आर्थिक व्यवस्था की लगाम छूट चुकी है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने सोने की खरीद को लेकर सरकार की अपील पर भी कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि जनता तो वैसे भी डेढ़ लाख तोले का सोना खरीदने की स्थिति में नहीं है, बल्कि भाजपा के लोग ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसकी जानकारी 'लखनऊ से लेकर गोरखपुर' और 'अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी'

तक ली जा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि सारी पाबंदियां चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों याद आईं। अखिलेश ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने हजारों चार्टर विमान यात्राएं कीं, महंगे होटलों में ठहरे और बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल किया। ऐसे में जनता पर ही प्रतिबंध और अपीलें थोपना उचित नहीं है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की इस तरह की अपीलों से बाजार में भय, घबराहट और मंदी की आशंका पैदा होगी।

सरकार का काम संकट से उबारना होता है, न कि अफरातफरी का माहौल बनाना। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विदेश नीति और गृह नीति दोनों मोर्चों पर विफल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनावी राजनीति को प्रदूषित कर दिया है और समाज में नफरत फैलाकर सौहार्द को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक हर क्षेत्र में भाजपा की नीतियों से देश को नुकसान हुआ है। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता अब भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुकी है और वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब बदलाव चाहती है।

वर्क फ्रॉम होम के लिए क्यों कहा?

पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि हम वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग जैसी सेवाओं को फिर शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान भी पेट्रोल और डीजल की किफायत से जुड़ा है। क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस से फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा। लोगों की घर से दफ्तर आवाजाही कम होगी। बिजली और तेल का कुल इस्तेमाल कम होगा और बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर खाने में तेल के उपयोग में कुछ कमी करें तो वो भी देशभक्ति का काम है। इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के लोगों का भी स्वास्थ्य सुधरेगा। भारत खाने के तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। भारत पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल को आयात करता है। भारत इंडोनेशिया, मलेशिया अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से खाने के तेल (कुकिंग ऑयल) को आयात करता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी कुल खाद्य तेल (कुकिंग ऑयल/एडेबल ऑयल) जरूरत का लगभग 55% से 60% आयात करता है और इस क्रम में भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से अपील की कि केमिकल फर्टिलाइजर पर अपनी निर्भरता कम करें. भारत दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर (उर्वरक) उपभोक्ताओं में है। यूरिया, डीएपी, पोटाश, और इनके कच्चे माल का बड़ा हिस्सा भारत आयात करता है। इनकी कीमतें जुड़ी होती हैं- प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल, और वैश्विक सप्लाई चेन से यानी अगर पश्चिम एशिया संकट से तेल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, शिपिंग प्रभावित होती है, तो उर्वरक भी महंगे हो जाते हैं। भारत में किसान सस्ती कीमत पर खाद खरीदते हैं क्योंकि सरकार भारी सब्सिडी देती है। ऐसे में अगर फर्टिलाइजर यानी खाद की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार का सब्सिडी बिल बहुत बढ़ जाता है।

बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार

बंगाल-पुडुचेरी में जीती भाजपा, असम में हैट्रिकः तमिलनाडु में एक्टर विजय बनेंगे सीएम; केरलम में कांग्रेस लौटी, लेफ्ट सरकार अब देश में कहीं नहीं

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा का कमल खिल चुका है। भाजपा ने टीएमसी को पटखनी देते हुए 206 सीटें हासिल की हैं। वहीं, तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा सियासी झटका देते हुए अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। हालांकि, बिना गठबंधन के राज्य में विजय की सरकार नहीं बनेगी।

उधर, असम में भाजपा ने सीएम हिमंत बिस्वा

अनादि शुक्ल

सरमा के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाई है। असम में एनडीए को 102 सीटें मिली हैं। वहीं, देश में वाम दलों का आखिरी किला कहे जाने वाले केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इधर, पुदुचेरी में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हुई है। सीएम एन रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनने जा रही है।

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में चार मई की तारीख ने नया अध्याय जोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने जहां राज्य को भगवा रंग में रंगने का भाजपा-जनसंघ का सात दशक पुराना स्वप्न साकार कर दिया। वहीं तमिलनाडु में लोकप्रिय अभिनेताओं को सिर आंखों पर बिठाने की परंपरा फिर जीवित हो गई और तमिल सिनेमा के

सुवेंदु अधिकारी
मुख्यमंत्री (पश्चिम बंगाल)

डॉ. हिमंत बिस्वा
मुख्यमंत्री (असम)

एन. रंगासामी
मुख्यमंत्री (पुडुचेरी)

पिनाराई विजयन
मुख्यमंत्री (केरल)

विजय थलापति
मुख्यमंत्री (तमिलनाडु)

सुपरस्टार थलापति विजय की पहली बार चुनाव में उतरी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम यहां सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एमके स्टालिन तक चुनाव हार गए। इस तरह, विपक्ष के दो बड़े चेहरों को इस चुनाव ने गहरा झटका दिया है।

बंगाल में ढहा तृणमूल का किला

भाजपा की आंधी में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का किला तिनके की तरह बिखर गया। भाजपा ने 206 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। बंगाल में सरकार न बना पाने की संघ-भाजपा के नेतृत्व की टीस भी खत्म हो गई। जनसंघ के संस्थापकों में शुमार और भाजपा के प्रेरणा-पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृहराज्य पश्चिम बंगाल में आखिर कमल खिल गया। 2011 के विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली भाजपा ने अनथक संघर्ष के जरिये तृणमूल कांग्रेस के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया। तृणमूल महज 80 सीटों पर सिमट गई, जो पिछले चुनाव में भाजपा की 77 सीटों से सिर्फ तीन अधिक है। भाजपा की ओर से सीएम पद के सबसे सशक्त उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के साथ भवानीपुर सीट पर कांटे के मुकाबले में ममता खुद हार गईं। उनके 20 मंत्री भी हार गए। शुभेंदु भवानीपुर के साथ नंदीग्राम से भी चुनाव जीत गए हैं।

असम में चला हिमंत का जादू

असम में भाजपा की जीत को लेकर किसी को कोई संशय नहीं था। सवाल सिर्फ यही था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा कितनी सीटों तक पहुंचाएंगे। राज्य में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। सहयोगियों को भी दस-दस सीटों पर विजय मिली। जीत की हैट्रिक लगाने वाली भाजपा ने 126 सदस्यीय विधानसभा में अपने दम पर 82 सीटें जीती हैं, जबकि सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 10-10 सीटें मिली हैं। इस तरह एनडीए ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। मुख्यमंत्री हिमंत के कट्टर विरोधी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को जोरहाट सीट पर भाजपा विधायक हितेंद्रनाथ गोस्वामी से 23,181 वोटों से करारी हार मिली। वहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को सिर्फ दो सीटें मिलीं।

तमिलनाडु में थलापति की विजय

पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से आई, जहां सुपरस्टार विजय चंद्रशेखर ने दो ध्रुवीय द्रविड़ियन राजनीति को जोरदार पटखनी दी है। मात्र दो साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) को उन्होंने सत्ता की दहलीज पर पहुंचा दिया। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके ने 107 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। वह बहुमत से सिर्फ 11 सीटें दूर है। टीम लीडर यानी थलापति के रूप में प्रसिद्ध विजय की इस जीत ने राज्य में फिर से अभिनेताओं को सत्ता सौंपने की परंपरा जीवित कर दी। टीवीके के शानदार प्रदर्शन के बीच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी –भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कल शाम दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीस से अधिक राज्यों में भाजपा–एनडीए सरकारें सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का मंत्र है 'नागरिक ही भगवान है' और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि जनता इसीलिए पार्टी पर अधिकाधिक भरोसा जता रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि जहां भाजपा है, वहां सुशासन और विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए एक नए सवेरे का आगमन हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि असम की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा–एनडीए पर भरोसा जताया है और यह एक हैट्रिक है। उन्होंने इसे असम के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि बताया। रिकॉर्ड मतदान का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने चुनावों के सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन आयोग, उसके अधिकारियों, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को बधाई दी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों के परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता के अटूट समर्थन और विश्वास को दशार्ते हैं। श्री नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह शानदार जीत पार्टी कार्यकताओं के अथक प्रयासों और समर्पण का परिणाम है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनाव हार गए। स्टालिन को कोलाथुर में टीवीके उम्मीदवार वीएस बाबू ने 8,795 वोटों के अंतर से हराया। हालांकि स्टालिन के बेटे और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि जीत गए। सरकार के 15 मंत्री भी हार गए।

केरलम में वाम दलों का आखिरी किला भी ढहा, सीएम विजयन जीत

देश में वामपंथी दलों का आखिरी किला ढह गया। केरलम में दो चुनाव में जीत हासिल करने वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) को करारी हार मिली है। सीएम पी विजयन ने रविवार रात ही सोशल मीडिया पर सीएम वाला अपना बायो हटा दिया था। केरलम के मतदाताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) पर भरोसा जताते हुए 140 सदस्यीय विधानसभा में उसे 99 सीटें सौंप दी। केरलम अब देश में कांग्रेस शासित चौथा राज्य हो जाएगा। माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को 35 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री पी विजयन ने धर्मदम से कांग्रेसी वीपी अब्दुल रशीद को 19,247 वोटों से हराया। छठे दौर की गिनती तक विजयन पीछे चल रहे थे। विजयन के 21 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस को अपने दम पर 63 सीटें मिली हैं, जबकि उसके गठबंधन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसने 22 सीटें जीती हैं।

पुदुचेरी में उम्मीदों के अनुरूप एनडीए सरकार की वापसी, टीवीके ने भी खोला खाता

केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी को लेकर किसी को कोई अंदेशा नहीं था। मुख्यमंत्री एन रंगासामी की पार्टी एआईएनआर कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है और नतीजों ने इसे सही साबित किया। तीस सदस्यीय विधानसभा में एआईएनआर कांग्रेस को 12, भाजपा को चार व अन्नाद्रमुक को एक सीट मिली है। पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री रंगासामी ने मंगलम सीट पर द्रमुक के एसएस रंगन को हराया। विपक्षी द्रमुक गठबंधन में द्रमुक को 5 जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली है। खास यह है, तमिलनाडु में शानदार जीत हासिल करने वाली टीवीके ने यहां भी खाता खोल लिया। उसे दो सीटें मिली हैं। निर्दलीय व अन्य ने 5 सीटें जीती हैं। अतीत में पुडुचेरी में अक्सर उस पार्टी की जीत होती रही है, जिसकी तमिलनाडु में सरकार हो, पर पिछले दो बार से यह ट्रेंड बदल गया।

तमिलनाडु में 'थलापति युग' का उदय

रवि जैन

तमिलनाडु की राजनीति में वर्ष 2026 को एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। लगभग छह दशकों तक राज्य की राजनीति पर वर्चस्व रखने वाली द्रविड़ पार्टियों-डीएमके और एआईएडीएमके - के बीच पहली बार किसी तीसरी शक्ति ने सत्ता के शिखर तक पहुँचने का कारनामा किया है। फिल्म अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ थलापति विजय ने अपनी पार्टी टीवीके (तमिलगा वेत्री कड़गम) के माध्यम से न केवल सत्ता परिवर्तन किया, बल्कि तमिल राजनीति की पूरी दिशा बदल दी। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर विजय ने यह संदेश दिया कि उनकी लोकप्रियता केवल सिनेमाई परदे तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक धरातल पर भी गहरी पैठ बना चुकी है।

फ्लोर टेस्ट : सत्ता की पहली बड़ी परीक्षा

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों से पीछे रह गई। इसके बाद शुरू हुआ समर्थन जुटाने का राजनीतिक अभियान। मुख्यमंत्री विजय ने डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन, पीएमके नेता अंबुमणि रामदास और एमडीएमके नेताओं से मुलाकात कर समर्थन का वातावरण तैयार किया।

अंततः विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला और सरकार ने विश्वास मत जीत लिया।

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत : सेतुपति प्रकरण' बना राजनीतिक ड्रामा

फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले टीवीके विधायक आर. श्रीनिवासन सेतुपति को मद्रास हाई कोर्ट ने विश्वास मत में भाग लेने से रोक दिया था। इस आदेश ने तमिल राजनीति में भूचाल ला दिया। मामला तत्काल सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, जहाँ शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की टिप्पणी को 'अत्यंत अनुचित' बताते हुए विधायक को मतदान की अनुमति दे दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट राहत न देता तो विजय सरकार के लिए स्थिति जटिल हो सकती थी।

क्या राहुल गांधी बने किंगमेकर'?

तमिल राजनीति के इस नए समीकरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने सबसे पहले टीवीके को समर्थन देकर डीएमके से दूरी बनाई और सत्ता समीकरण बदल दिए। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे राहुल गांधी की रणनीतिक चाल मान रहे हैं। उनका आकलन है कि कांग्रेस ने दक्षिण भारत में अपने लिए नई राजनीतिक जमीन तैयार करने के उद्देश्य से विजय को समर्थन दिया। विश्लेषकों का एक वर्ग राहुल गांधी को इस पूरे घटनाक्रम में 'संकटमोचक' और 'किंगमेकर' की भूमिका में देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के शुरूआती समर्थन के बाद अन्य छोटे दलों

और निर्दलीय विधायकों का रुझान भी विजय की ओर बढ़ा।

क्या केंद्र और राज्यपाल बने विलेन'?

टीवीके समर्थक लगातार आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार और राज्यपाल कार्यालय सरकार गठन की प्रक्रिया को कठिन बनाने का प्रयास कर रहे थे। हालाँकि संवैधानिक विशेषज्ञों का मत है कि राज्यपाल द्वारा बहुमत परीक्षण की मांग करना भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। फिर भी टीवीके समर्थकों ने इसे 'नई राजनीतिक शक्ति को रोकने का प्रयास' बताकर जनभावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ा। अभिनेता की लोकप्रियता या राजनीतिक रणनीति? विजय की जीत के पीछे क्या था असली कारण?

विजय मंत्रिमंडल : करोड़पति और दागदार चेहरे?

विजय मंत्रिमंडल में कुल 10 मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने गृह, पुलिस और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि कई मंत्री संपन्न कारोबारी पृष्ठभूमि से आते हैं और करोड़पति हैं। विपक्ष ने कुछ मंत्रियों पर पुराने विवादों और कथित आपराधिक मामलों को लेकर प्रश्न उठाए हैं, हालांकि इन मामलों में अंतिम न्यायिक निर्णय शेष हैं।

ड्राइवर के बेटे को मंत्री बनाने का फैसला

विजय सरकार के सबसे चर्चित निर्णयों में एक रहा - अपने पुराने ड्राइवर के पुत्र को मंत्री पद देना। टीवीके समर्थकों ने इसे 'सामाजिक न्याय और अवसर की राजनीति' बताया। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह 'भावनात्मक राजनीति' का हिस्सा है। लेकिन आम जनता के एक वर्ग में इस निर्णय ने सकारात्मक संदेश दिया कि नई सरकार सामाजिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर अवसर देना चाहती है।

ज्योतिषी को सरकारी पद देने पर विवाद

मुख्यमंत्री विजय द्वारा अपने ज्योतिषीय सलाहकार को सरकारी दायित्व दिए जाने की खबरों ने भी राजनीतिक विवाद पैदा किया। विपक्ष ने इसे 'वैज्ञानिक सोच के विरुद्ध' बताया, जबकि टीवीके समर्थकों का कहना है कि भारतीय राजनीति में आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सलाह कोई नई बात नहीं।

जनता की उम्मीदों पर कितने खरे?

तमिलनाडु में विजय के प्रति जनता की अपेक्षाएँ असाधारण रूप से ऊँची हैं। उनकी छवि एक ईमानदार, सरल और भ्रष्टाचार-विरोधी नेता की बनाई गई है। फिलहाल जनता उन्हें 'मौका देने' के मूड में दिखाई देती है, लेकिन आने वाले महीनों में प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था उनके राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेंगे।

तमिल राजनीति का नया अध्याय

तमिलनाडु की राजनीति में यह परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मनोविज्ञान का बड़ा बदलाव माना जा रहा है। द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक द्विध्रुवीय ढाँचे को तोड़ते हुए टीवीके ने यह सिद्ध किया है कि जनता अब नए विकल्पों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ी चुनौती विजय के सामने यही है कि वे 'सुपरस्टार' की लोकप्रियता को 'सफल प्रशासक' की विश्वसनीयता में कितनी तेजी से बदल पाते हैं। यदि वे ऐसा कर पाए, तो दक्षिण भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरूआत मानी जाएगी।

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार विजय की सफलता के पीछे कई कारण रहे

1. अभिनेता की विराट जनस्वीकार्यता
   विजय वर्षों से तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में रहे हैं। युवाओं और ग्रामीण वर्ग में उनकी पकड़ अत्यंत मजबूत रही।
2. सामाजिक सेवा की दीर्घ तैयारी
   पिछले ढाई-तीन वर्षों में टीवीके ने रक्तदान शिविर, छात्र सहायता, आपदा राहत और गरीब परिवारों के लिए चिकित्सा सहायता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक सामाजिक आधार तैयार किया।
3. एंटी-इंकम्बेंसी फैक्टर
   डीएमके और एआईएडीएमके के लंबे राजनीतिक वर्चस्व से जनता का एक वर्ग बदलाव चाहता था।
4. पेशेवर चुनावी प्रबंधन
   राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रही कि चुनावी रणनीतिकारों और डेटा-आधारित चुनाव अभियान ने टीवीके को आधुनिक राजनीतिक बढ़त दी। कई विश्लेषक इसमें प्रशांत किशोर शैली की चुनावी रणनीति की झलक देखते हैं, यद्यपि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।

चुनावी वादे : कितने पूरे हुए?

सरकार बनने के तुरंत बाद विजय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं -

- **200 यूनिट मुफ्त बिजली**
- **महिला सुरक्षा टास्क फोर्स**
- **एंटी-ड्रग विशेष अभियान**
- **युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम**
- **सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार**

हालाँकि अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग इन योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठा रहा है।

योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार: 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की नैय्या पार?

मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर गूर्जर समाज से आते हैं, डॉक्टर तोमर सरल स्वभाव के शानदार राजनेता हैं, फिलहाल वह योगी सरकार में राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का कार्यभार देख रहे हैं, कैबिनेट विस्तार में उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है।

प्रवीण सिंह कुशवाहा

राजनीतिक गुणा-भाग व विधानसभा चुनावों के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से लंबित चले आ रहे यूपी कैबिनेट के विस्तार पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की आखिरकार मौहर लग ही गई। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गयी थी। शनिवार शाम 9 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद से ही कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले चहरों के वारे में राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे थे। वहीं लखनऊ स्थित जन भवन में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी शासन-प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार 10 मई 2026 की दोपहर 3.30 बजे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 6 नये चहरों भूपेंद्र चौधरी व मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेन्द्र दिलेर व हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया, वहीं अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ाते हुए उन्हें राज्य मंत्री की जगह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। हालांकि यूपी कैबिनेट विस्तार में कई पुराने चेहरों को हटाकर के कुछ नये चहरों को शामिल करने की देश व प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा चल रही थी, राजनेताओं व राजनीतिक विश्लेषकों की यूपी कैबिनेट विस्तार

कि लिस्ट पर निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो किसी भी पुराने चेहरों को मंत्रीमंडल से हटाएं बिना ही 6 नये चहरों को मंत्रीमंडल में शामिल किया गया और दो राज्य मंत्रियों का प्रमोशन करते हुए उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस यूपी कैबिनेट विस्तार में कुछ चर्चित चेहरों के नाम अंतिम समय में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के राजनीतिक गुणा-भाग की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहे, जिसके चलते अंतिम समय में उनके नाम कैबिनेट विस्तार की राज्यपाल के पास जाने वाली लिस्ट में बाहर हो गये।

इस कैबिनेट विस्तार में शामिल राजनेताओं के प्रोफाइल पर संक्षिप्त नजर डालें तो कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी वर्ष 2017-2022 वाली योगी सरकार में भी पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं और वह भाजपा के निवर्तमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वह राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी और बड़े जाट नेता के रूप में स्थापित माने जाते हैं। वहीं तेजतर्रार, व्यवहार कुशल, दबंग विधायक मनोज पांडेय ब्राह्मण समाज से आते हैं, वह रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, वह सपा की अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा के चुनावों में खुलकर के भाजपा प्रत्याशी का साथ दिया था, जिसके बाद उन्हें सपा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर के ईनाम दिया गया है। उनकी ताजपोशी से भाजपा के नेतृत्व स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भाजपा सहयोग करने वालों का हमेशा ध्यान रखती है।

मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर गूर्जर समाज से आते हैं, डॉक्टर तोमर सरल स्वभाव के शानदार राजनेता हैं, फिलहाल वह योगी सरकार में राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का कार्यभार देख रहे हैं, कैबिनेट विस्तार में उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव निरंतर गूर्जर वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर तोमर के प्रमोशन को गूर्जर वोटरों को साधने की भाजपा नेतृत्व की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

वहीं कानपुर देहात के सिकंदरा से भाजपा के विधायक अजीत पाल फिलहाल योगी सरकार में राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कार्य देख रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद की शपथ दिलाई है।

वहीं कैबिनेट विस्तार में शामिल राज्य मंत्रियों की बात करें तो कन्नौज के तिर्वा से विधायक विधायक कैलाश सिंह राजपूत, वाराणसी में भाजपा के जिलाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, अलीगढ़ के खैर से भाजपा के विधायक सुरेंद्र दिलेर, फतेहपुर के खागा से भाजपा की विधायक कृष्णा पासवान ने पहली बार राज्यमंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ ली है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को योगी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार से बहुत उम्मीदें हैं।

हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले त्यागी समाज के हाथ इस बार के कैबिनेट विस्तार में भी खाली ही रहे, जबकि त्यागी समाज के एक मात्र विधायक अजीत पाल त्यागी व विधान परिषद सदस्य अश्विनी त्यागी दोनों में से कम से कम एक का नाम कैबिनेट विस्तार की इस लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट विस्तार का लक्ष्य वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक, सामाजिक, जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए योगी सरकार के पक्ष में जबरदस्त उत्साहपूर्ण माहौल बनाने का है। वहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फामूर्ला तोड़ करते हुए योगी सरकार के पक्ष में ब्राह्मण, ओबीसी, दलित व अन्य सभी सनातनियों को एकजुट करना है। हालांकि यह तो आने वाला समय ही बताएगा की भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इसमें राजनीतिक गुणा-भाग में कितना सफल होगा, लेकिन जनता की अदालत में बार-बार के चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट है कि मोदी, शाह व योगी की लोकप्रियता व चाणक्य नीति की काट का अभी देश में विपक्षी दलों के पास कोई विकल्प नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

कैसे तय किया संन्यासी से मुख्यमंत्री तक का सफर?

बीजेपी नेताओं के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ न सिर्फ हिंदुत्व बल्कि सुशासन के भी प्रतीक हैं और उनके शासन के दौरान गुंडों और माफियाओं को उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा है

संजीव कुमार

भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन 5 जून को मनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कैसे भाजपा में मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम कैसे मिला, इससे जुड़ी कुछ बातें जानते हैं।

पौड़ी गढ़वाल में हुआ था जन्म

योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून, 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार के सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वह ऋषिकेश आ गए। यहां वह गोरक्षपीठ के प्रमुख महंत अवैद्यनाथ से मिले और उनके शिष्य बन गए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही चार दर्जन से ज्यादा शिक्षण, स्वास्थ्य एवं धर्मार्थ संस्थाओं के संचालक और संरक्षक भी हैं। योगी आदित्यनाथ पहली बार 12वें लोकसभा चुनाव के दौरान 1998 में गोरखपुर से सांसद बने थे। इसके बाद 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा में भी गोरखपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस दौरान वह संसद में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। योगी आदित्यनाथ साल 2017 से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य हैं। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर 'The Monk Who Became Chief Minister' बायोग्राफी लिखने वाले शांतनु गुप्ता बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने बचपन में वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता ली थी लेकिन वह उसकी विचारधारा से प्रभावित नहीं हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए।

महंत अवैद्यनाथ से मिले योगी

शांतनु गुप्ता अपनी किताब में लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान गोरखपुर मठ में महंत अवैद्यनाथ से मिले। महंत अवैद्यनाथ योगी आदित्यनाथ से बहुत प्रभावित हुए और उस दौरान धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग

योगी आदित्यनाथ को 'छोटे महंत' के नाम से जानने लगे थे।

1994 में बनाया गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी

योगी आदित्यनाथ को उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ ने साल 1994 में गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी बनाया था। उत्तराधिकारी बनने के बाद उनका नाम योगी आदित्यनाथ रखा गया। वह नाथ संप्रदाय के प्रमुख और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ ने कई स्कूलों और कॉलेज के साथ ही अस्पताल का भी संचालन किया। संन्यासी के रूप में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया।

1996 में उनका राजनीति से जुड़ाव तब शुरू हुआ जब उन्हें महंत अवैद्यनाथ के चुनाव अभियान का प्रभारी बनाया गया। जब महंत अवैद्यनाथ 1998 में सक्रिय राजनीति से विदा हुए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया।

2002 में बनाई हिंदू युवा वाहिनी

योगी आदित्यनाथ जातियों और क्षेत्रों में बंटे हिंदू समुदाय को एकजुट करने का आह्वान करते रहे हैं। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। इस संगठन में शामिल स्वयंसेवकों ने गो रक्षा, लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की। 2005 में योगी आदित्यनाथ ने 'घर वापसी' नाम से शुद्धिकरण अभियान चलाया और इसके तहत हिंदू धर्म छोड़कर गए लोगों की उनके मूल धर्म में वापसी कराई गई। इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर रहे, उन्हें जेल जाना पड़ा। 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में बड़े हिंदू चेहरे के रूप में सामने आए हैं। असम से लेकर तमिलनाडु और तमाम प्रदेशों में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती रही है।

हिंदुत्व के साथ ही सुशासन के प्रतीक

समर्थकों के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ न सिर्फ हिंदुत्व बल्कि सुशासन के भी प्रतीक हैं और उनके राज में उत्तर प्रदेश में आम आदमी के भीतर इस बात का भरोसा बढ़ा है कि कोई भी अपराधी या माफिया उन्हें परेशान नहीं कर सकता। बीजेपी कार्यकताओं का यह भी दावा है कि माफिया और गुंडों को उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा है। उनके शासन के दौरान उत्तर प्रदेश ने गुंडा और माफिया राज को पीछे छोड़कर विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में अलग पहचान बनाई है।

अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि अपराध, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के खिलाफ उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं, व्यापारियों से लेकर आम लोगों की सुरक्षा तक में सेंध लगाने वाले किसी भी शख्स से कानून पूरी सख्ती से निपटेगा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए ही साल 2025 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा महाकुंभ लगा। महाकुंभ के दौरान 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। इस दौरान किए गए इंतजामों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार

के कामकाज की तारीफ हुई। कोरोना की महामारी के दौरान ही 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन, स्वास्थ्य सेवाएं, लाखों लोगों को क्वॉरेंटाइन करने का काम भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में बखूबी हुआ है। उनके समर्थक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहकर पुकारते हैं।

'यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी' का नारा

2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर ह्यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी' का नारा देकर योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर मुहर लगाई थी। प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों की कई बार तारीफ की है। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश धार्मिक पर्यटन से लेकर तमाम विषयों पर काफी काम किया है। समर्थकों के मुताबिक, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने और बड़े पैमाने पर निवेश भी हुआ। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए ही भाजपा और एनडीए ने 2022 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब जब 9 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सूबे में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।

न रोड पर ईद की नमाज और न कोई लाउडस्पीकर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यूपी में पहली बार सड़कों पर ईद की नमाज नहीं हुई और मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज भी कम हो गई है।

मजदूर दिवस की कहानी: इतिहास संघर्ष और अधिकारों की दास्तां

श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और एकजुटता का प्रतीक 1 मई यानी मई दिवस दुनिया भर के मजदूरों के लंबे संघर्षों की याद दिलाता है। आज जिस आठ घंटे के कार्यदिवस को सामान्य माना जाता है, वह मजदूरों को यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे अनगिनत संघर्ष, हड़तालें, जेलें और शहादतें जुड़ी हैं।

19 वीं सदी में अमेरिका सहित कई देशों में मजदूरों से 14 से 18 घंटे तक काम कराया जाता था। काम के घंटों का कोई निश्चित नियम नहीं था। महिलाएं और बच्चे भी कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने को मजबूर थे। जो मजदूर विरोध करते, उन पर मालिकों के गुंडे, पुलिस और सेना तक छोड़ दी जाती थी।

इन्हीं हालातों के खिलाफ अमेरिका के मजदूरों ने संगठित होकर आवाज उठाई। 1877 से 1886

हरेन्द्र शर्मा

के बीच आठ घंटे काम, आठ घंटे आराम और आठ घंटे अपने जीवन के लिए समय की मांग तेज होती गई। 1886 में देशभर में मजदूरों ने 'आठ घंटे समितियां' बनाईं। इस आंदोलन का सबसे मजबूत केंद्र बना शिकागो।

1 मई 1886 को अमेरिका के लाखों मजदूरों ने एक साथ हड़ताल शुरू कर दी। करीब 11 हजार फैक्ट्रियों के 3 लाख 80 हजार से अधिक मजदूर इसमें शामिल हुए। शिकागो में रेल यातायात ठप हो गया, कारखाने बंद हो गए और मजदूरों ने विशाल जुलूस निकाला।

मजदूरों की बढ़ती ताकत से उद्योगपति घबरा उठे। अखबारों ने मजदूर आंदोलन को 'लाल खतरा' बताकर प्रचार शुरू किया। शहर में भारी

पुलिस बल तैनात किया गया। कुख्यात पिंकरटन एजेंसी के हथियारबंद गुंडों को भी मजदूरों पर हमला करने के लिए बुलाया गया।

3 मई को शिकागो के मैकार्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी के मजदूरों ने दो महीने से चल रहे लॉकआउट के खिलाफ प्रदर्शन किया। जब हड़ताली मजदूरों ने हड़ताल तोड़ने लाए गए लोगों के खिलाफ सभा शुरू की, तभी पुलिस ने निहत्थे मजदूरों पर गोलियाँ चला दीं। चार मजदूर मारे गए और कई घायल हुए।

इस बर्बर दमन के विरोध में अगले दिन 4 मई की शाम को शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में जनसभा बुलाई गई।

सभा में करीब तीन हजार लोग शामिल हुए। मजदूर नेताओं अल्बर्ट पार्सन्स, ऑगस्ट स्पाइस और सैमुअल फील्डेन ने मजदूरों से एकजुट रहने की अपील की। रात लगभग दस बजे सभा समाप्ति की ओर थी, तभी 180 पुलिसकर्मियों का दल वहां पहुंचा और भीड़ को हटने का आदेश दिया।

इसी दौरान अचानक एक बम फेंका गया। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि बम किसने फेंका। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह साजिश मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए रची गई थी। बम से एक पुलिसकर्मी मारा गया और कई घायल हुए।

इसके बाद पुलिस ने चारों ओर से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। छह मजदूर मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए। मजदूरों ने अपने खून से रंगे कपड़ों को ही झंडा बना लिया। यही लाल झंडा आगे चलकर मजदूर एकता का प्रतीक बना।

हेमार्केट घटना के बाद शिकागो में मजदूर बस्तियों, दफ्तरों और छापाखानों पर छापे मारे गए। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। आठ मजदूर

नेताओं पर हत्या का झूठा मुकदमा चलाया गया। अल्बर्ट पार्सन्स पुलिस से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अदालत में स्वयं पहुंचकर कहा– 'मैं अपने बेकसूर साथियों के साथ कठघरे में खड़ा होने आया हूं।' 20 अगस्त 1887 को अदालत ने सात नेताओं को फांसी और एक को 15 साल कैद की सजा सुनाई।

11 नवंबर 1887 मजदूर वर्ग के इतिहास में काला दिन बन गया। अल्बर्ट पार्सन्स, ऑगस्ट स्पाइस, एंजेल और फिशर को शिकागो की जेल में फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि चारों नेता क्रांतिकारी गीत गाते हुए फांसी के तख्ते तक पहुंचे और पूरे साहस के साथ मौत का सामना किया। 13 नवंबर को उनकी शवयात्रा विशाल जनसैलाब में बदल गई।

पांच लाख से अधिक लोग इन शहीद नेताओं को अंतिम सलाम देने सड़कों पर उमड़ पड़े।

हेमार्केट शहीदों की याद में 1889 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ने फैसला किया कि हर वर्ष 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तब से दुनिया भर में यह दिन मजदूरों के अधिकार, सम्मान, एकता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

मई दिवस हमें याद दिलाता है कि अधिकार कभी दान में नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। आठ घंटे काम का अधिकार, न्यूनतम वेतन, छुट्टी, सुरक्षा और सम्मान–इन सबके पीछे मजदूरों का लंबा संघर्ष छिपा है। आज भी जब श्रमिक अधिकारों पर खतरे बढ़ रहे हैं, तब मई दिवस की यह कहानी हमें एकजुट होकर न्याय और बराबरी की लड़ाई जारी रखने का संदेश देती है।

NEET पर फिर उठे सवाल

पेपर लीक, परीक्षा निरस्तीकरण और युवाओं के भविष्य पर सियासी संग्राम तेज

प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने विद्यार्थियों के बीच मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ाई है।

NEET परीक्षा रद्द होने और उसमें कथित गड़बड़ियों के मुद्दों को लेकर बोलते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी शिकायतों ने लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार हो रहे परीक्षा घोटाले देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं।

देशभर में लगभग 22 से 23 लाख विद्यार्थियों ने NEET-UG परीक्षा दी थी। ऐसे में परीक्षा की विश्वसनीयता पर उठे प्रश्नों ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा तंत्र पर

कपिल शर्मा

व्यापक बहस छेड़ दी है।

'युवाओं का भविष्य भ्रष्टाचार की भेंट' - प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा शासन में बीते कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि NEET जैसी परीक्षा के लिए विद्यार्थी वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं और माता-पिता अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, लेकिन हर बार परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रियंका गांधी ने पूछा कि संसद में पारित कथित कठोर एंटी-पेपर लीक कानून का वास्तविक लाभ क्या हुआ, यदि जमीनी स्तर पर परीक्षाओं में धांधली नहीं रुक पा रही है।

राहुल गांधी ने केंद्र से मांगी जवाबदेही

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी NEET विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि 'NEET के लाखों बच्चों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर मौन हैं।' राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग करते

- राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर उठे गंभीर प्रश्न

हुए कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो इसकी जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की टिप्पणी - "Modi ji, SACK Dharmendra Pradhan ji NOW" - व्यापक चर्चा का विषय बनी रही।

परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बढ़ती चिंता

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा निरस्तीकरण के मामलों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बीते वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों ने विद्यार्थियों के बीच मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ाई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा संचालन, डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली और जवाबदेही तंत्र को भी पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा।

विपक्ष ने उठाए बड़े सवाल

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से कई प्रश्न पूछे हैं -

- **आखिर बार-बार परीक्षा सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है?**
- **पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए कानून कितने प्रभावी हैं?**
- **दोषियों के खिलाफ अब तक कितनी कठोर कार्रवाई हुई?**
- **लाखों छात्रों की मेहनत और मानसिक दबाव की भरपाई कौन करेगा?**

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं और शिक्षा से जुड़ा यह मुद्दा आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है।

पेपर लीक और परीक्षा निरस्तीकरण के विरोध में देशभर में छात्रों और अभिभावकों के बीच बढ़ती चिंता और आक्रोश।

केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार पर शीघ्र कार्यवाही की मांग पर बोलते हुए सांसद प्रियंका गांधी।

छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी बेचैनी

देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। कई छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है और केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग तेज हो गई है।

अभिभावकों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाएँ केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों और भविष्य का आधार हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही पूरे समाज के विश्वास को कमजोर करती है।

नीट यू जी: सिस्टम के आगे लाचार युवाओं के सपने

ब्रिज पंवार

सिस्टम के आगे लाचार युवाओं के सपनेआज मई की इस तपती दोपहर में देश का भविष्य,हमारा युवा,सड़कों पर खड़ा है। दिल्ली का जंतर-मंतर हो या पटना की गलियाँ, हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, 'न्याय दो!' यह केवल सिस्टम से हताश छात्रों का प्रदर्शन मात्र नहीं है। यह उस भरोसे का टूटना है, जो एक साधारण भारतीय परिवार अपने बच्चे की मेहनत, ईमानदारी और सपनों पर करता है। 2024 का घाव अभी भरा भी नहीं था।

ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जनमानस और छात्रों के आक्रोश के बीच सरकार ने सुधारों का भरोसा दिया, समितियाँ बनीं, नई सुरक्षा तकनीकों की घोषणाएँ भी हुईं। लेकिन 2026 में फिर वही खबरें सामने हैं,छापेमारी, सॉल्वर गैंग, गिरफ्तारियाँ और लीक हुए प्रश्नपत्र। तब सवाल उठना स्वाभाविक है किआखिर गलती कहाँ है? सिस्टम में, नीयत में, या उन लोगों में जिन्होंने शिक्षा को कारोबार बना दिया है?

आज सीबीआई राजस्थान के सीकर से लेकर महाराष्ट्र के नासिक तक छापेमारी कर रही है। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं कि दोषी कौन है। असली प्रश्न यह है कि हमारा सिस्टम इतना खोखला कैसे हो गया कि 25 लाख छात्रों का भविष्य कुछ माफियाओं की तिजोरियों का गुलाम बन गया।

हम किस 'डिजिटल इंडिया' की बात करते हैं, जब देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक को भी पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित नहीं कर पा रहे? तथाकथित तौर पर अचूक रूप से सुरक्षित प्रणाली बनाने की घोषणा की जाती है,करोड़ों रुपये अक निगरानी, बायोमेट्रिक्स, जैमर्स और जी पी एस ट्रैकिंग पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन प्रश्नपत्र फिर भी लीक हो जाता है! इसका अर्थ साफ है किसमस्या बाहर नहीं, भीतर है। दीमक दीवारों पर नहीं, नींव में बैठ चुकी है। समस्या का सबसे भयावह पक्ष यह है कि यह अब कोई स्थानीय गिरोह नहीं रह गया।

बिहार से हरियाणा, राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैले सॉल्वर नेटवर्क अब शिक्षा व्यवस्था के समानांतर एक 'अंडरग्राउंड इंडस्ट्री' बन चुके हैं।

परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सऐप पर प्रश्नपत्र तैरने लगते हैं। यह तकनीकी गलती नहीं, बल्कि सुनियोजित संगठित अपराध है। दुनिया के विकसित देशों में मेडिकल और उच्च स्तरीय परीक्षाएँ पूर्णतः डिजिटल और एन्क्रिप्टेड मॉडल पर आधारित हैं।

चीन की गाओकाओ (Gaokao) और अमेरिका की SAT जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक की कल्पना भी राष्ट्रीय संकट मानी जाती है। भारत आज भी करोड़ों प्रश्नपत्र छापकर ट्रकों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक भेजने की पुरानी व्यवस्था पर निर्भर है। जब प्रश्नपत्र भौतिक रूप से यात्रा करेंगे, तब लीक की खिड़कियाँ खुली ही रहेंगी। इस संकट का दूसरा पक्ष शिक्षा का खतरनाक बाजारीकरण है। कई कोचिंग संस्थान अब शिक्षा के मंदिर नहीं, बल्कि 'रैंक फैक्ट्री' में बदल चुके हैं। गारंटीशुदा चयन के विज्ञापन, टॉपर पैकेजेस और रिजल्ट मार्केटिंग की अंधी दौड़ ने शिक्षा के नैतिक आधार को कमजोर कर दिया है।

जब सफलता केवल रैंक से मापी जाएगी, तब ईमानदारी धीरे-धीरे हाशिए पर चली जाएगी।अब केवल 'कड़ी निंदा' और 'जांच के आदेश' से काम नहीं चलेगा। यदि सचमुच बदलाव चाहिए, तो परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सी बी टी (CBT: Computer Based Test) आधारित बनाना होगा। प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले एन्क्रिप्टेड डिजिटल सर्वर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएँ। पेपर लीक में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त हो, फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई हो, और सजा ऐसी हो कि अगली पीढ़ियाँ भी याद रखें। सरकार को यह समझना होगा कि छात्र कोई वोट बैंक नहीं हैं। वे इस देश की रीढ़ हैं। यदि यही रीढ़ टूट गई, तो विकसित भारत का सपना केवल भाषणों तक सीमित रह जाएगा।

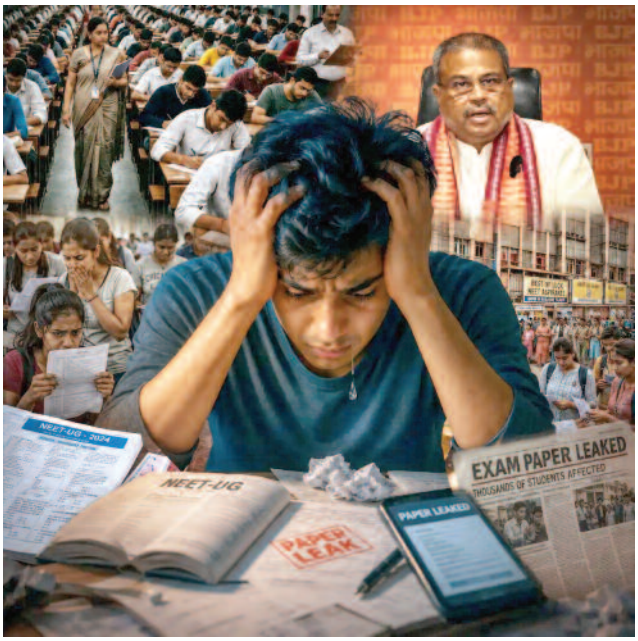

एनटीए (NTA) के अधिकारियों को कभी उस छात्र की आँखों में झाँकना चाहिए, जिसने गाँव की बिजली कटौती के बीच लालटेन जलाकर पढ़ाई की,जिसके परिवार ने कर्ज लेकर उसे कोचिंग कराई,और अंत में उसके हाथ क्या आया? एक लीक हुआ पेपर! एक रद्द परीक्षा! और टूटता हुआ विश्वास! साहब, अब समय मरहम का नहीं, सर्जरी का है। क्योंकि जब युवाओं का भरोसा टूटता है, तब केवल एक परीक्षा नहीं हारती,पूरा राष्ट्र हारने लगता है।

केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है पत्रकारिता की स्वतंत्रता

सचिन तोमर

मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत अहम माना गया है लेकिन विड़म्बना है कि विगत कुछ वर्षों से यहां भी प्रेस स्वतंत्रता के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। इसीलिए प्रतिवर्ष 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है।

भारत में प्रेस को सदैव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी जाती रही है क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत अहम माना गया है लेकिन विड़म्बना है कि विगत कुछ वर्षों से यहां भी प्रेस स्वतंत्रता के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। इसीलिए प्रतिवर्ष 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। कलम को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर और तलवार की धार से भी ज्यादा प्रभावी इसीलिए माना गया है क्योंकि इसी की सजगता के कारण न केवल भारत में बल्कि अनेक देशों में पिछले कुछ दशकों के भीतर बड़े-बड़े घोटालों का पदार्फाश हो सका, जिसके चलते बड़े-बड़े उद्योगपतियों, नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आना पड़ा। यही कारण हैं कि समय-समय पर कलम रूपी इस हथियार को भोथरा बनाने या तोड़ने के कुचक्र होते रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में सच की कीमत कुछ पत्रकारों को

अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। पिछले दशकों में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में स्थितियां काफी बदल गई हैं। आज दुनियाभर में पत्रकारों पर राजनीतिक, अपराधिक और आतंकी समूहों का सर्वाधिक खतरा है और भारत भी इस मामले में अछूता नहीं है। विड़म्बना है कि दुनियाभर के न्यूज रूम्स में सरकारी तथा निजी समूहों के कारण भय और तनाव में वृद्धि हुई है।

पेरिस स्थित 'रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स' (आरएसएफ) अथवा 'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' नामक संस्था द्वारा हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, वे सदैव चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि कुछ देश इस रिपोर्ट में जारी किए जाने वाले आंकड़ों को पूर्वाग्रह से प्रेरित बताकर खारिज भी करते रहे हैं।

'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' एक ऐसा गैर-लाभकारी संगठन है, जो विश्वभर के पत्रकारों पर हमलों का दस्तावेजीकरण करने और मुकाबला करने के लिए कार्यरत है और प्रतिवर्ष 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' अर्थात 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' नामक रिपोर्ट पेश करता है। 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019' में उसने भारत सहित विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया था कि किस प्रकार विश्वभर में पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है, जिससे दुनियाभर में पत्रकारों में डर बढ़ा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के अनुसार, 180 देशों की सूची में भारत 157वें स्थान पर खिसक गया है जबकि 2025 में भारत 151वें स्थान पर था यानी एक वर्ष में छह स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पूर्व 2024 में भारत 159वें, 2023 में 161वें और 2022 में 150वें पायदान पर खड़ा था। यह रिपोर्ट प्रेस स्वतंत्रता के लिए भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट का संकेत देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के साथ व्यवहार के लिए 'संतोषजनक' माने जाने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है लेकिन ऐसी संख्या भी कम नहीं है, जहां स्थिति 'बहुत गंभीर' है।

रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स द्वारा जारी दुनियाभर के देशों की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत जहां 2024 में 2023 के मुकाबले दो पायदान ऊपर चढ़ा, वहीं 2023 में 2022 के मुकाबले 11 पायदान नीचे गिरा था और 2022 में भी 2021 की रैंकिंग के मुकाबले 8 स्थान नीचे फिसला था। 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की सूची में नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत के लोकतंत्र को तो दुनिया का सबसे सफल और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहीं अगर नार्वे जैसा छोटा सा देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में लगातार शीर्ष स्थान पर विराजमान है और चीन को छोड़कर भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश भी बेहतर स्थिति में है तो यह स्थिति भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए सही स्थिति नहीं है। ऐसे में हमें गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है कि हम इस मामले में वर्ष दर वर्ष क्यों फिसल रहे हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में यह गिरावट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत यही है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। समाज में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ माना गया है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार खासकर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बगैर किसी जानकारी को जांचे-परखे केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठ का बवंडर तैयार किया जाता है, उसे देखकर कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है मानो टीवी चैनल पर समाचार या कोई न्यूज कार्यक्रम नहीं बल्कि कोई मसालेदार राजनीतिक फिल्म चल रही हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है कि लोगों का विश्वास मीडिया पर निरंतर कम हो रहा है और लोगों का आकर्षण सोशल मीडिया की ओर बढ़ रहा है, जहां पहले से ही फेक न्यूज बहुत बड़ी समस्या मौजूद है तथा एआई इस समस्या को और ज्यादा बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रही है।

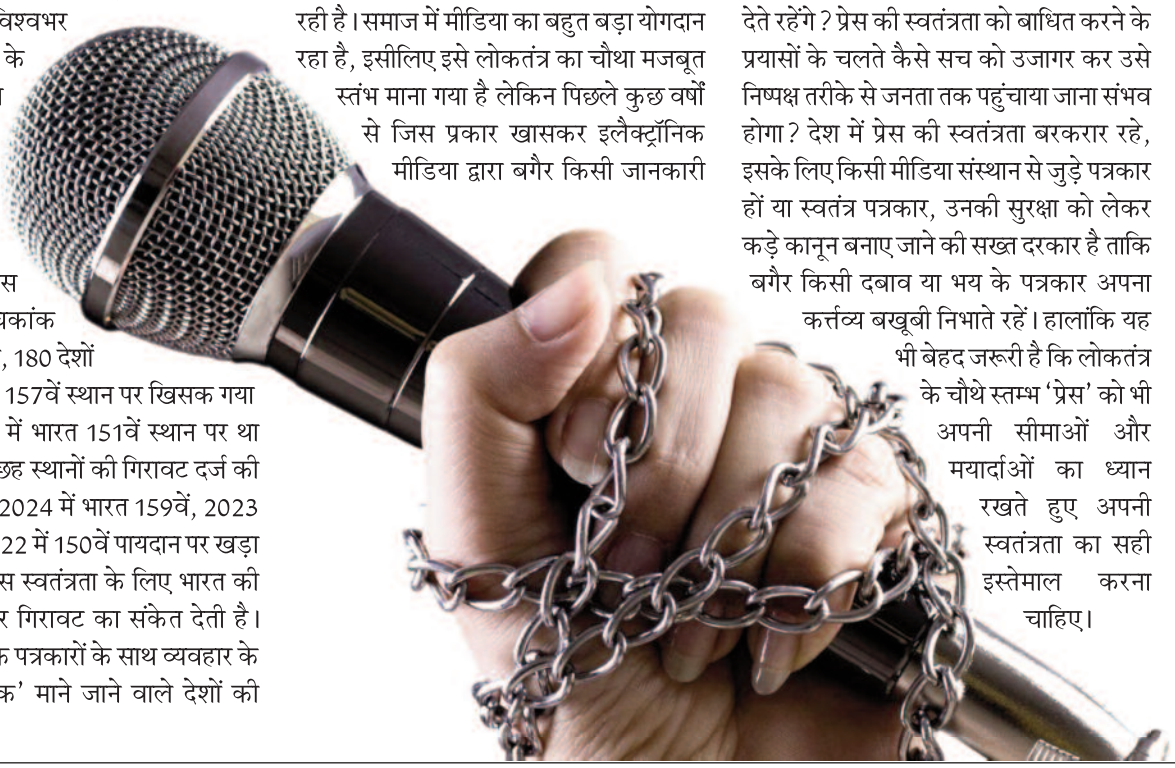

भारतीय संविधान में प्रेस को अलग से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता में ही निहित है और देश की एकता तथा अखण्डता खतरे में पड़ने की स्थिति में इस स्वतंत्रता को बाधित भी किया जा सकता है किन्तु ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होने पर भी देश में पत्रकारिता का चुनौतीपूर्ण बनते जाना लोकतंत्र के हित में कदापि नहीं है बल्कि यह स्पष्ट रूप से कुछ शक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का ही प्रयास माना जाता है। कल्पना की जा सकती है कि प्रेस की स्वतंत्रता अगर इसी प्रकार सवालों के घेरे में रही तो पत्रकार कैसे पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे? प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के प्रयासों के चलते कैसे सच को उजागर कर उसे निष्पक्ष तरीके से जनता तक पहुंचाया जाना संभव होगा? देश में प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रहे, इसके लिए किसी मीडिया संस्थान से जुड़े पत्रकार हों या स्वतंत्र पत्रकार, उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए जाने की सख्त दरकार है ताकि बगैर किसी दबाव या भय के पत्रकार अपना कर्त्तव्य बखूबी निभाते रहें। हालांकि यह भी बेहद जरूरी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ 'प्रेस' को भी अपनी सीमाओं और मयार्दाओं का ध्यान रखते हुए अपनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करना चाहिए।

चाय पर बुलाकर पीठ में छुरा, लद्दाख की आवाज दबाने के लिए LG दफ्तर का 'ट्वीट-धोखा'

अशोका होटल के जश्न के बीच सरहद पर तानाशाही: सोनम वांगचुक को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही सरकार, LG बोले- 'भड़काऊ नैरेटिव न गढ़ें', मैग्सेसे विजेता का पलटवार- 'आकाओं को खुश करने के लिए बदला बयान'

अजीत शर्मा

दिल्ली के आलीशान होटलों में जब सत्ता का कुनबा अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने की रूपरेखा तय कर रहा है, ठीक उसी वक्त देश की बर्फीली सरहद लद्दाख पर लोकतंत्र को बंधक बनाने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। लद्दाख की स्वायत्तता और पर्यावरण की रक्षा के लिए हाड़ कंपाने वाली ठंड में अनशन करने वाले 'धरती पुत्र' सोनम वांगचुक के साथ देश के गृह मंत्रालय और लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना के दफ्तर ने एक ऐसा 'छल' किया है, जिसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। पहले लद्दाख के अधिकारों की मांग करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जैसी दमनकारी धाराओं के तहत जेल में ठूंसना, फिर आंदोलन को कुचलने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां-गोलियां बरसाना और अब बातचीत के बहाने बुलाकर पीठ के पीछे भ्रामक नैरेटिव गढ़ना- यह वर्तमान व्यवस्था का नया चरित्र बन चुका है।

चाय का निमंत्रण या 'सेंसरशिप' की सरकारी वॉर्निंग?

विवाद की शुरूआत तब हुई जब लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो को गृह मंत्रालय में 'चाय और चर्चा' के लिए आमंत्रित किया। वांगचुक के मुताबिक, लगभग एक घंटे तक बेहद सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी के माहौल में लद्दाख के विकास और हिम सरोवर जैसी परियोजनाओं पर सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी कि लद्दाख का माहौल शांतिपूर्ण रखा जाए।

'मुझे चाय के लिए बुलाया गया था, पर्यावरण पर अच्छी बातें हुईं। लेकिन हमारे निकलने के एक घंटे बाद LG का जो ट्वीट आया, उसे देखकर मेरे भरोसे का फालूदा हो गया। वो ट्वीट ऐसा था मानो मुझे चाय नहीं, बल्कि दिल्ली के आकाओं के इशारे पर डराने और फटकारने के लिए बुलाया गया हो।'

— सोनम वांगचुक,
पर्यावरण कार्यकर्ता व शिक्षाविद्

लेकिन वांगचुक के कमरे से निकलते ही उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट दाग दिया, जो पूरी तरह झूठ और भ्रामक दावों से भरा था। एलजी ने दावा किया कि उन्होंने वांगचुक को 'भ्रामक और भड़काऊ नैरेटिव गढ़ने' के खिलाफ चेताया है और वांगचुक ने माना है कि लद्दाख की तुलना मणिपुर से करना उनकी 'निर्णय की भूल' थी।

'मैं आज भी मानद कॉकरोच हूँ': सरकारी इनसिक्योरिटी पर वांगचुक का करारा तमाचा

सरकार की सबसे बड़ी छटपटाहट युवाओं के ऑनलाइन आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) को लेकर है, जिसे वांगचुक का समर्थन हासिल है। सरकारी तंत्र ने इस आंदोलन को कुचलने

आखिर सरकार क्यों डरती है सोनम वांगचुक से?

लद्दाख का दर्द	सरकारी वादे बनाम जमीनी हकीकत
बेरोजगारी का विस्फोट	धारा 370 हटने के बाद लद्दाख में बेरोजगारी की दर 21% तक बढ़ गई है। युवा नौकरियों के लिए तरस रहे हैं।
छठी अनुसूची	भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि लद्दाख को आदिवासी सुरक्षा कवच (6th Schedule) देंगे, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं किया।
अधिकारविहीन UT	देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का दर्जा घटाकर उसे बिना विधानसभा वाली वळ बनाया गया, जहां जनता की कोई आवाज नहीं है और सारी शक्तियां एक ब्यूरोक्रेट (LG) के हाथ में हैं।
आबादी बड़ी, प्रतिनिधित्व छोटा	सिक्किम से बड़ी आबादी होने के बावजूद लद्दाख के पास लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है, जबकि वहां कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए।

के लिए हमेशा की तरह घिसा-पिटा 'विदेशी ताकतों और पाकिस्तानी फंडिंग' का नैरेटिव आगे कर दिया। एलजी ने दावा किया कि वांगचुक इस पार्टी से दूरी बना रहे हैं। इस सरकारी दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ाते हुए सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर कहा, 'मैं मन ही मन एलजी की इन कहानियों पर हंस रहा था। ये वही कहानियां हैं जो आठ महीने पहले मुझे जेल में डालते वक्त मेरे खिलाफ गढ़ी गई थीं कि मेरे संबंध पाकिस्तान से हैं। सरकारें ऑनलाइन असहमति से इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती हैं? अगर देश का युवा पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा नीति पर मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहा है, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।' वांगचुक ने साफ किया कि वह खुद को गर्व से 'ऑनरेरी कॉकरोच' (मानद कॉकरोच) मानते हैं और इस रचनात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ मजबूती से खड़े हैं।

थ्री इडियट्स के 'फुंसुख वांगडू' से लद्दाख के 'महानायक' बनने तक का सफर

परिचय और पहचान: सोनम वांगचुक भारत के एक प्रख्यात मैकेनिकल इंजीनियर, प्रर्वतक (Innovato) और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। वह लद्दाख की दुर्गम वादियों में शिक्षा और पर्यावरण की अलख जगाने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं।

लाइमलाइट में आगमन (दशकों का संघर्ष): उन्होंने 1988 में SECMOL (स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख) की स्थापना की, जिसने लद्दाख के सरकारी स्कूलों में फेल होने वाले 95% बच्चों की तकदीर बदल दी। उनके इस अभूतपूर्व सामाजिक सुधार के लिए उन्हें एशिया का नोबेल माने जाने वाले 'रैमन मैग्सेसे पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

बॉलीवुड का 'फुंसुख वांगडू' कनेक्शन: बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 Idiots' में आमिर खान द्वारा निभाया गया आइकॉनिक और कालजयी

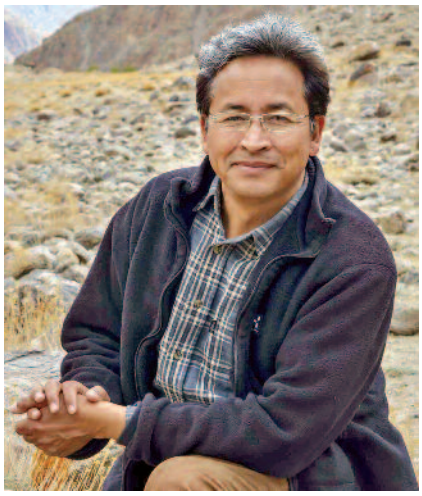

किरदार 'Phunsukh Wangdu' (फुंसुख वांगडू) असल जिंदगी में सोनम वांगचुक के जीवन, उनकी सोच और उनके आविष्कारों से ही पूरी तरह प्रेरित था।

क्लाइमेट फास्ट (जमीन की लड़ाई): वांगचुक तब देश के मानस पटल पर छा गए जब उन्होंने माइनस 40 डिग्री तापमान में लद्दाख के नाजुक पर्यावरण और ग्लेशियरों को उद्योगपतियों के हाथों बेचे जाने के खिलाफ 21 दिनों का कठोर 'क्लाइमेट फास्ट' (अनशन) किया।

सरहद पर पानी और जिंदगी बचाने वाले आविष्कार

आइस स्तूप (Ice Stupa): हिमालयी क्षेत्रों में पानी की भीषण किल्लत और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए उन्होंने 'आइस स्तूप' नामक कृत्रिम ग्लेशियर (ArtificiÔl Glacier) का आविष्कार किया। यह सर्दियों में बेकार बहने वाले पानी को बर्फ के विशाल पहाड़ों में जमा देता है, जो गर्मियों में पिघलकर खेती के लिए वरदान साबित होते हैं। इस खोज के लिए उन्हें वैश्विक स्तर पर 'रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज' मिला।

इको-फ्रेंडली आर्किटेक्चर: उन्होंने लद्दाख की मिट्टी से ऐसे सोलर-हीटेड मिट्टी के घर (Solar Heated Mud Buildings) बनाए, जो सर्दियों में बिना किसी हीटर या कोयले के, बाहर माइनस 20 डिग्री तापमान होने पर भी अंदर से गर्म (प्लस 20 डिग्री) रहते हैं।

गोली चलाने का आदेश किसने दिया? नागरिक संगठनों ने दागे तीखे सवाल

'हम भारत के लोग' और 'NAPM' जैसे राष्ट्रीय नागरिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख का दौरा करने के बाद केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। संगठनों ने पूछा कि पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक और उनके साथियों पर 24 तारीख को बर्बर हिंसा क्यों की गई? जब कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं थी, तो सीने और सिर पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

नागरिक संगठनों ने कहा, 'सोनम वांगचुक कोई अमृतपाल नहीं हैं जिन्हें लद्दाख से उठाकर जबरन राजस्थान की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वाले पर्यावरणविदों और युवाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाना तानाशाही की पराकाष्ठा है। सरकार को तुरंत वांगचुक और गिरफ्तार किए गए 45 स्थानीय नागरिकों को बिना शर्त रिहा करना चाहिए।' लद्दाख की जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस लद्दाख ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने का स्वागत इस उम्मीद में किया था कि उन्हें अधिकार मिलेंगे, आज उन्हें एक अदद रोजगार मांगने पर लाठियां और जेल मिल रही है। दिल्ली के हुक्मरानों को यह समझना होगा कि सरहद की सुरक्षा केवल बख्तरबंद गाड़ियों से नहीं, बल्कि सरहद पर रहने वाले नागरिकों का दिल जीतकर होती है।

तपती कक्षाएँ और संवेदनहीन व्यवस्था

एन के शर्मा

भारत इस समय भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। हर वर्ष तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। मौसम विभाग लगातार हीट वेव की चेतावनियाँ जारी करता है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। सरकारी कार्यालयों, निजी कंपनियों, बैंक, मॉल और बड़े संस्थानों में कूलर और एयर कंडीशनर की व्यवस्था सामान्य बात हो चुकी है। कर्मचारियों की सुविधा और कार्यक्षमता के लिए वातानुकूलित वातावरण को आवश्यक माना जाता है। लेकिन जब बात स्कूलों की आती है तो तस्वीर अचानक बदल जाती है। देश के लाखों बच्चे और शिक्षक आज भी तपती हुई कक्षाओं में बैठकर दिन बिताने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है मानो व्यवस्था ने यह मान लिया हो कि केवल स्कूल के बच्चों और मास्टरों को ही गर्मी नहीं लगती।

यह केवल एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र की दुखद सच्चाई है। जिस देश में बच्चों को राष्ट्र का भविष्य' कहा जाता है, वहीं उन्हीं बच्चों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। शिक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, स्मार्ट क्लास, डिजिटल इंडिया और नई शिक्षा नीति की बातें होती हैं, लेकिन जब कोई सरकारी स्कूल की वास्तविक स्थिति देखता है तो सारे दावे खोखले दिखाई देते हैं। गर्मी के दिनों में कई सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी भट्ठी से कम नहीं होती। कहीं टीन की छतें धूप में तपकर आग उगलती हैं, कहीं छोटे-छोटे कमरों में दर्जनों बच्चे ठूँस दिए जाते हैं। कई स्कूलों में पंखे खराब पड़े रहते हैं, तो कहीं बिजली की ही व्यवस्था नहीं होती। खिड़कियाँ या तो टूटी होती हैं या इतनी छोटी कि हवा का प्रवेश ही न हो सके। ऐसे वातावरण में बच्चे घंटों बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं।

कल्पना कीजिए, जब बाहर तापमान 45 डिग्री के पार हो और भीतर बैठा बच्चा पसीने से तरबतर हो, तब उसका ध्यान किताबों में कैसे लगेगा? छोटे बच्चे बार-बार पानी पीने के लिए उठते हैं, कुछ बच्चों को चक्कर आने लगते हैं, कई बच्चे थकान और बेचैनी से परेशान हो जाते हैं। कई बार हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी घटनाएँ भी सामने आती हैं। इसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था में बैठे लोगों को यह समस्या शायद उतनी गंभीर नहीं लगती। शिक्षकों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। उन्हें उसी गर्म वातावरण में लगातार कई पीरियड लेने होते हैं। बोर्ड पर लिखना, बच्चों को संभालना और पढ़ाना, यह सब आसान नहीं होता। लेकिन विडंबना यह है कि जिन शिक्षकों पर भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी है, उनकी कार्य परिस्थितियों पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है।

यदि किसी सरकारी कार्यालय का एसी खराब हो जाए तो शिकायत तुरंत दर्ज होती है और मरम्मत

की व्यवस्था भी जल्दी हो जाती है। कर्मचारियों की सुविधा को कार्य दक्षता' से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के लिए कूलर या एसी की बात होते ही अक्सर यह कह दिया जाता है कि इतनी सुविधाएँ संभव नहीं हैं' या यह अनावश्यक खर्च है।' सवाल यह है कि क्या बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा कम महत्वपूर्ण है? यदि आरामदायक वातावरण किसी कर्मचारी की कार्यक्षमता बढ़ा सकता है, तो वही वातावरण बच्चों की सीखने की क्षमता और मानसिक एकाग्रता को क्यों नहीं बढ़ाएगा?

आज बड़े शहरों के निजी स्कूलों में एयर कंडीशनर युक्त कक्षाएँ आम होती जा रही हैं। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक सुविधाएँ मिलती हैं। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों के बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। यह केवल सुविधा का अंतर नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता का जीवंत उदाहरण है। एक तरफ अमीर बच्चों के लिए ठंडी और स्मार्ट कक्षाएँ हैं, दूसरी तरफ गरीब परिवारों के बच्चे तपती दीवारों और पसीने भरे कमरों में बैठने को मजबूर हैं। शिक्षा में समानता की बातें करने वाला समाज इस असमानता पर अक्सर चुप दिखाई देता है।

शिक्षा केवल किताबों, परीक्षाओं और पाठ्यक्रम का नाम नहीं है। सीखने के लिए एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण भी उतना ही आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से यह बताते आए हैं कि अत्यधिक गर्मी बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक सक्रियता को प्रभावित करती है। गर्म वातावरण में बच्चा जल्दी थक जाता है और उसकी सीखने की क्षमता कम हो जाती है। जब बच्चा पूरे समय गर्मी से परेशान रहेगा, तो वह पाठ पर ध्यान कैसे केंद्रित करेगा? शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को स्कूल भेजना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा वातावरण देना है जहाँ वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर सीख सकें।

विडंबना यह है कि सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए करोड़ों रुपये डिजिटल योजनाओं पर खर्च करती हैं, लेकिन कक्षाओं के तापमान पर शायद ही कभी चर्चा होती है। जबकि सच्चाई यह है कि गर्मी से जूझता बच्चा स्मार्ट बोर्ड से अधिक एक ठंडी हवा की जरूरत महसूस करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति तो और भी अधिक चिंताजनक है। कई गाँवों में बिजली की आपूर्ति ही नियमित नहीं होती। कुछ स्कूलों में आज भी पर्याप्त कमरे नहीं हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे या खुले बरामदों में बैठकर पढ़ते हैं। ऐसे स्थानों पर कूलर या एसी की कल्पना करना भी कठिन लगता है। कई स्कूलों में पीने के पानी की समस्या भी गंभीर होती है। गर्मियों में पानी के टैंक सूख जाते हैं या पानी इतना गर्म हो जाता है कि पीना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को कई बार दूर से पानी लाना पड़ता है। यह स्थिति केवल असुविधा नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

हर वर्ष शिक्षक दिवस, बाल दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर नेताओं के भाषणों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया जाता है। बच्चे देश का भविष्य हैं' जैसी पंक्तियाँ बार-बार दोहराई जाती हैं। लेकिन वास्तविक प्राथमिकताएँ स्कूलों की स्थिति देखकर समझी जा सकती हैं। यदि वास्तव में बच्चे देश का भविष्य हैं, तो क्या उन्हें कम से कम इतना

देश के लाखों बच्चे और शिक्षक आज भी तपती हुई कक्षाओं में बैठकर दिन बिताने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है मानो व्यवस्था ने यह मान लिया हो कि केवल स्कूल के बच्चों और मास्टरों को ही गर्मी नहीं लगती।

अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वे सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें? क्या यह उचित है कि कार्यालयों की सुविधाएँ प्राथमिकता बन जाएँ और बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएँ उपेक्षित रह जाएँ?

यह समस्या केवल संसाधनों की नहीं, बल्कि सोच की भी है। हमारे समाज में अक्सर बच्चों और शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यह मान लिया गया है कि स्कूलों में थोड़ी असुविधा सामान्य' है। यही सोच सबसे बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में गर्मी लगातार बढ़ रही है। कई शहरों में तापमान 47-48 डिग्री तक पहुँच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में हीट वेव की घटनाएँ और अधिक बढ़ेंगी। ऐसे में स्कूलों की पारंपरिक व्यवस्था अब पर्याप्त नहीं रह गई है। आज आवश्यकता है कि स्कूल भवनों का निर्माण मौसम के अनुसार किया जाए। पर्याप्त वेंटिलेशन, हरे पेड़, ठंडे छत डिजाइन, स्वच्छ पेयजल और तापमान नियंत्रण जैसी सुविधाएँ अनिवार्य हों। यह विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है।

सरकार यदि चाह ले तो चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों में कूलर और बेहतर पंखों की व्यवस्था की जा सकती है। सौर ऊर्जा आधारित समाधान भी अपनाए जा सकते हैं। कई राज्यों में मिड-डे मील, स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा जैसी योजनाएँ सफलतापूर्वक लागू हुई हैं, तो बच्चों को गर्मी से राहत देने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए संवेदनशील सोच और वास्तविक प्राथमिकता की जरूरत है। केवल घोषणाओं और विज्ञापनों से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी।

समाज को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। हम अक्सर अपने बच्चों के लिए निजी स्कूलों की सुविधाएँ देखते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को सामान्य मान लेते हैं। सामाजिक संगठनों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और अभिभावकों को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

हमारे समाज में शिक्षक को गुरु' कहकर सम्मान दिया जाता है। शिक्षक दिवस पर बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं। लेकिन वास्तविक सम्मान केवल भाषणों और फूलों से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब शिक्षक को बेहतर कार्य परिस्थितियाँ दी जाएँ। जो शिक्षक स्वयं गर्मी, थकान और असुविधा से जूझ रहा हो, उससे सर्वोत्तम प्रदर्शन की अपेक्षा करना उचित नहीं है। यदि हम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं, तो शिक्षकों के कार्य वातावरण को बेहतर बनाना ही होगा।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी कक्षाओं में तैयार होता है। यदि वे कक्षाएँ ही तपती भट्टियों में बदल जाएँ, तो विकास के सारे दावे खोखले लगने लगते हैं। बच्चे केवल आँकड़े नहीं होते, वे सपने होते हैं। और सपनों को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षा को केवल नीतियों और भाषणों का विषय न बनाएँ, बल्कि उसकी वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान दें। बच्चों और शिक्षकों को भी वही सम्मान और सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो समाज के अन्य वर्गों को मिलती हैं। क्योंकि सच यही है– जिस देश के बच्चे तपती कक्षाओं में बैठने को मजबूर हों, वहाँ विकास की चमक अधूरी ही मानी जाएगी।

'कर्मयोगी' : सुशासन और विकास के दो स्तंभ

गाजियाबाद की 'वैश्विक पहचान' और पीलीभीत की 'बुनियादी क्रांति' के शिल्पकार

प्रशासन जब केवल सत्ता का केंद्र न रहकर जनसेवा का माध्यम बन जाए, तो शहरों की सूरत और सीरत दोनों बदल जाती हैं। उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण जनपदों गाजियाबाद और पीलीभीत में आज विकास की जो बयार बह रही है, उसके पीछे दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी कार्यशैली से 'सुशासन' को नई परिभाषा दी है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक जहां अपनी खेल भावना और आधुनिक विजन से शहर को वैश्विक मंच (ब्लूमबर्ग चैलेंज) पर ले जा रहे हैं, वहीं पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधार कर 'अंत्योदय' के सपने को धरातल पर उतारा है। इन दोनों अधिकारियों की कार्यक्षमता ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति से बड़ी से बड़ी चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है।

प्रशासक, खिलाड़ी और विजनरी...

गाजियाबाद के कायाकल्प के 'शिल्पी' विक्रमादित्य सिंह मलिक

ललित कुमार

उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त और औद्योगिक शहरों में शुमार 'गाजियाबाद' आज एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। धूल, धुएं और भीड़भाड़ वाले शहर की पहचान अब 'स्मार्ट और सस्टेनेबल' सिटी के रूप में हो रही है। इस बदलाव के केंद्र में है एक युवा, ऊर्जावान और खेल भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व विक्रमादित्य सिंह मलिक (IAS)। वर्तमान में गाजियाबाद के नगर आयुक्त के रूप में कार्यरत विक्रमादित्य ने न केवल फाइलों के बोझ को कम किया है, बल्कि शहर की नसों में विकास का नया रक्त संचारित किया है।

पारिवारिक विरासत और प्रारंभिक संघर्ष, सादगी से सफलता का सफर

विक्रमादित्य सिंह मलिक का व्यक्तित्व उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रतिबिंब है। चंडीगढ़ के एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक परिवार में जन्मे विक्रमादित्य के रगों में जनसेवा की भावना विरासत में मिली है। उनके पिता, युद्धवीर सिंह मलिक

शिक्षा और लॉ से आईएएस तक का सफर

विक्रमादित्य ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही यह साबित कर दिया था कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ-साथ वे खेलों में भी सक्रिय रहे। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित नालसार यूनिवर्सिटी, हैदराबाद से कानून की डिग्री हासिल की। वकालत के पेशे में कदम रखा और एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में अनुभव भी लिया। लेकिन साल 2012 में उनकी बहन के आईएएस बनने के बाद, उनके भीतर की जनसेवा की लौ और तेज हो गई। सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं था। दो बार की असफलता ने उन्हें निराश जरूर किया, लेकिन उनकी 'स्पोर्ट्समैन स्पिरिट' ने उन्हें हार नहीं मानने दी। साल 2017 में उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में अखिल भारतीय स्तर पर 48वीं रैंक हासिल कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया।

(IAS), हरियाणा कैडर के एक दिग्गज अधिकारी रहे हैं, जिनकी कार्यशैली की छाप विक्रमादित्य पर स्पष्ट दिखती है। उनकी माता एक प्रख्यात लेखिका हैं, जिनसे उन्हें रचनात्मक सोच और संवेदनशीलता मिली।

'ब्लूमबर्ग मेयर चैलेंज 2025' और ग्लोबल पहचान

विक्रमादित्य सिंह मलिक की सबसे बड़ी वैश्विक उपलब्धि तब आई जब गाजियाबाद का चयन प्रतिष्ठित 'ब्लूमबर्ग मेयर चैलेंज 2025' के लिए हुआ। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। उनका विजन था 'ऑर्गेनिक वेस्ट' यानी गीले कचरे को 'व्हाइट रूफटॉप पेंट' में बदलना। यह इनोवेशन न केवल कचरा प्रबंधन का समाधान देता है, बल्कि शहरों के तापमान को कम करने में भी क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट ने गाजियाबाद को दुनिया के नक्शे पर एक 'इनोवेटिव सिटी' के रूप में स्थापित कर दिया है।

गाजियाबाद की वायु पर 'विजय' प्रदूषण के विरुद्ध जंग

जब विक्रमादित्य सिंह मलिक ने गाजियाबाद नगर निगम की कमान संभाली, तो सबसे बड़ी चुनौती थी शहर की हवा। गाजियाबाद अक्सर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर रहता था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत मिशन के तौर पर लिया।

मैकेनाइज्ड स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग: उन्होंने धूल से निपटने के लिए आधुनिक सड़कों की सफाई और पेड़ों पर पानी के छिड़काव को एक नियमित प्रक्रिया बनाया।

ग्रीन कवर का विस्तार: शहर के डिवाइडरों, पार्कों और खाली पड़ी जमीनों पर सघन पौधारोपण अभियान चलाकर उन्होंने 'ग्रीन गाजियाबाद' की नींव रखी।

GRAP का कड़ाई से पालन: निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपायों और कूड़ा जलाने पर भारी जुमार्ने जैसी सख्त कार्रवाइयों ने गाजियाबाद की वायु गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार दिखाया।

अतिक्रमण मुक्त गाजियाबाद: 'अवैध' पर प्रहार, 'विकास' को विस्तार

शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना किसी चुनौती से कम नहीं था। विक्रमादित्य ने 'अपील और एक्शन' का रास्ता चुना।

अवैध रैंप और अतिक्रमण: उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, उन्हें शहर के प्रति उनकी जिम्मेदारी समझाई और फिर जहां जरूरत पड़ी, वहां निगम का बुलडोजर चलाकर सड़कों को चौड़ा और सुगम बनाया।

सिस्टम में पारदर्शिता: हाउस टैक्स और व्यावसायिक कर की प्रणालियों को सरल और डिजिटल बनाकर उन्होंने भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म किया। 15 मार्च तक कर छूट की नीतियों को स्पष्ट कर उन्होंने आम जनता को बड़ी राहत दी।

नाम: विक्रमादित्य सिंह मलिक (IAS 2017)
रैंक: 48वीं (ऑल इंडिया)
शिक्षा: कानून में स्नातक (NALSAR, हैदराबाद)
प्रमुख पद: मुख्य विकास अधिकारी (CDO), नगर आयुक्त (गाजियाबाद)
विशेष उपलब्धि: ब्लूमबर्ग मेयर चैलेंज 2025 में चयन।
हॉबी: लॉन टेनिस (नेशनल सिविल सर्विसेज प्लेयर)
मूल मंत्र: 'समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा बनिए।'

खेलों के प्रति अटूट प्रेम, फाइलों के बीच 'लॉन टेनिस' की चमक

काम के भारी दबाव और घंटों की बैठकों के बावजूद, विक्रमादित्य सिंह मलिक ने अपने भीतर के खिलाड़ी को कभी मरने नहीं दिया। वे मानते हैं कि खेल हमें अनुशासन और टीम वर्क सिखाते हैं, जो प्रशासन के लिए अनिवार्य है। हाल ही में उनका चयन नेशनल सिविल सर्विसेज की यूपी टीम के लिए हुआ है। वे लॉन टेनिस में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बचपन का पसंदीदा खेल 'लॉन टेनिस' अब उनके तनाव को कम करने का जरिया और फिटनेस का आधार है। एक आईएएस अधिकारी का खेल के प्रति यह समर्पण शहर के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

जन-सुनवाई और संवेदनशीलता, जनता का 'अपना' अधिकारी

नगर आयुक्त के रूप में विक्रमादित्य केवल ऑफिस तक सीमित नहीं रहते। वे सुबह-सुबह सड़कों पर उतरकर सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हैं और 'जनता दर्शन' के माध्यम से सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं। चाहे वह कूड़ा निस्तारण की समस्या हो या स्ट्रीट लाइट की, उनके पास हर समस्या का एक 'टाइम-बाउंड' समाधान होता है। विक्रमादित्य सिंह मलिक के नेतृत्व में गाजियाबाद नगर निगम आज एक 'सर्विस प्रोवाइडर' की तरह काम कर रहा है। उनकी कार्यशैली में कानून की बारीकी, प्रशासन की दृढ़ता और एक खिलाड़ी का धैर्य नजर आता है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि नीयत साफ हो और विजन वैश्विक, तो किसी भी शहर की तस्वीर बदली जा सकती है। गाजियाबाद के लिए विक्रमादित्य का कालखंड 'स्वर्ण अक्षरों' में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने शहर को केवल सुविधाएं नहीं दीं, बल्कि उसे एक 'आत्मसम्मान' और 'वैश्विक पहचान' भी दी है।

पीलीभीत: प्रकृति का गौरव और प्रगति का नया अध्याय

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के विजनरी नेतृत्व में विकास और संरक्षण का अद्भुत संगम

लुकमान

उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर अंकित जनपद पीलीभीत, अपनी मिट्टी की सोंधी खुशबू और बांसुरी की सुरीली धुन के लिए तो विख्यात रहा ही है, लेकिन आज इसकी पहचान का फलक कहीं अधिक विस्तृत हो चुका है। हिमालय की तलहटी में बसा यह जनपद आज एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जहां एक ओर 730 वर्ग किलोमीटर में फैला पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) अपनी प्राकृतिक जैव-विविधता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर

जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में यह जिला आधुनिक विकास की नई गाथा लिख रहा है।

हरियाली की गोद में पीलीभीत टाइगर रिजर्व

साल 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद, पीलीभीत ने वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर अपनी जगह बनाई। यहां के घने 'साल' के वन और तराई के घास के मैदान न केवल बाघों के लिए एक आदर्श आवास हैं, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के लिए भी फेफड़ों का काम करते हैं, यहां केवल बाघ ही नहीं, बल्कि दुर्लभ बारहसिंगा, तेंदुआ, पाढ़ा, और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। शारदा और खन्नौत जैसी नदियों का सानिध्य इसे एक जलीय स्वर्ग भी बनाता है। रोजगार और संरक्षण का सेतु पीलीभीत का चूका बीच (Chuka Beach) आज पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका

है। जंगल की शांति और वन्यजीवों की झलक पाने के लिए आने वाले पर्यटकों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा दी है। होमस्टे से लेकर स्थानीय गाइडों तक, यहां का पर्यटन अब जन-जन की आय का स्रोत बन रहा है।

नेतृत्व की कमान, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह का दूरदर्शी दृष्टिकोण

प्रशासनिक दक्षता और जन-संवाद का नया मॉडल

किसी भी जनपद की प्रगति का पहिया उसके प्रशासनिक मुखिया की सोच पर निर्भर करता है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने पीलीभीत की कमान संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया कि विकास केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धरातल पर उतरेगा।

कानून व्यवस्था और पारदर्शिता

एक सुरक्षित समाज ही विकास की नींव रख सकता है। जिलाधिकारी ने जिले में कानून

व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक और मानवीय संवाद का अनूठा मेल स्थापित किया है। थानों की कार्यप्रणाली से लेकर राजस्व मामलों के निपटारे तक, उनके कड़े रुख ने अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास पैदा किया है।

जनसुनवाई, समस्या का त्वरित समाधान

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सुलभता है। नियमित जनसुनवाई के माध्यम से वे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा सुनते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले औचक निरीक्षणों ने विभागों में कार्य-संस्कृति को बदला है। अब कर्मचारी कार्यालयों में समय पर मिलते हैं और फाइलों की पेंडेंसी कम हुई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की नींव

जिलाधिकारी का विशेष ध्यान सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और स्वास्थ्य केंद्रों की बेहतरी पर रहा है। 'मिशन कायाकल्प' के तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करना और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है।

संपादक की राय

प्रशासनिक इच्छाशक्ति और प्राकृतिक संपदा का यदि सही मेल हो जाए, तो कोई भी जनपद आदर्श बन सकता है। पीलीभीत इसका ज्वलंत उदाहरण है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की सराहना केवल उनके पद के कारण नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए जमीनी बदलावों के कारण होनी चाहिए। उनके नेतृत्व में पीलीभीत न केवल सुरक्षित है, बल्कि समृद्ध भी हो रहा है।

विकास और पर्यावरण, एक अनूठा संतुलन

अक्सर विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया है। प्रशासन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि आधारभूत ढांचे (सड़क, बिजली, पानी) का विकास करते समय पीलीभीत की प्राकृतिक संपदा को कोई नुकसान न पहुंचे। सड़कों के जाल से लेकर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन तक, हर योजना में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पीलीभीत को ओडीएफ प्लस श्रेणी में बनाए रखने और कचरा प्रबंधन के आधुनिक तरीकों को अपनाने में प्रशासन की सक्रियता सराहनीय है।

योजनाओं का धरातल पर उतरना

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा का ध्यान रखते हुए ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण और बिजली की निर्बाध आपूर्ति पर विशेष बल दिया गया है, वहीं पीलीभीत एक कृषि प्रधान जिला है। किसानों को समय पर खाद, बीज और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासन की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।

पीलीभीत आज एक ऐसे दौर में है जहां वह अपनी प्राचीन पहचान (बांसुरी और तराई) को संजोते हुए आधुनिक भारत की दौड़ में सबसे आगे खड़ा है। एक तरफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार है, तो दूसरी तरफ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह जैसा सक्षम नेतृत्व है, जो जिले को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।

करुणा, शांति और आत्मजागरण के प्रकाशस्तंभ हैं गौतम बुद्ध

अरुण शर्मा

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन केवल एक युग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि युगों-युगों तक मानवता के पथ को आलोकित करता है। गौतम बुद्ध ऐसे ही एक अद्वितीय प्रकाशस्तंभ हैं, जिनका करुणा, अहिंसा और आत्मजागरण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ढाई हजार वर्ष पूर्व था। बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिवस केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं, बल्कि आत्मबोध, समता और शांति के उस दिव्य संदेश का पुनर्स्मरण है, जिसकी आज के हिंसाग्रस्त और तनावपूर्ण विश्व को अत्यंत आवश्यकता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन अद्वितीय है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञानप्राप्ति और महापरिनिर्वाण- तीनों घटनाएं घटित हुईं। नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और कुशीनगर में निर्वाण को प्राप्त हुए। इस दृष्टि से यह दिन केवल एक महापुरुष का स्मरण नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता, जागरण और मुक्ति का प्रतीक है। आज विश्व के विभिन्न देशों-श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, कोरिया और भारत में इसे विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। श्रीलंका में 'वेसाक' के रूप में दीपों और करुणा के उत्सव के रूप में यह दिन विशेष रूप से उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

गौतम बुद्ध एक प्रकाशस्तंभ है, जिसका प्रकाश केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि भीतरी दुनिया को भी आलोकिक करता है। बुद्ध को सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक महामनीषी, देवपुरुष, सिद्ध-संन्यासी, समाज-सुधारक धर्मगुरु माना जाता हैं। बुद्ध को भगवान विष्णु का नौवां अवतार भी माना जाता है, इस दृष्टि से हिन्दू धर्म में भी वे पूजनीय है। उन्हें धर्मक्रांति के साथ-साथ व्यक्ति एवं विचारक्रांति के सूत्रधार भी कह सकते हैं। उनकी क्रांतिवाणी उनके क्रांत व्यक्तित्व की द्योतक ही नहीं वरन् धार्मिक, सामाजिक विकृतियों एवं अंधरूढ़ियों पर तीव्र कटाक्ष एवं परिवर्तन की प्रेरणा भी है, जिसने असंख्य मनुष्यों का

जीवन-निर्माण किया एवं उनकी जीवन दिशा को बदला। बुद्ध ने जब अपने युग की जनता को धार्मिक-सामाजिक, आध्यात्मिक एवं अन्य यज्ञादि अनुष्ठानों को लेकर अज्ञान में घिरा देखा, साधारण जनता को धर्म के नाम पर अज्ञान में पाया, नारी को अपमानित होते देखा, शुद्रों के प्रति अत्याचार होते देखे-तो उनका मन जनता की सहानुभूति में उद्वेलित हो उठा। लोकजीवन को ऊंचा उठाने के लिये उन्होंने जो हिमालयी प्रयत्न किये, वे अद्भुत और आश्चर्यकारी है। बुद्ध के अनुसार जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है।

गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वे एक राजकुमार थे, किन्तु जीवन के दुख-जरा, व्याधि और मृत्यु ने उनके अंतर्मन को विचलित कर दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजवैभव का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। कठोर तप और साधना के पश्चात उन्होंने पाया कि न तो भोग का मार्ग उचित है और न ही अत्यधिक तप का। उन्होंने 'मध्यम मार्ग' का सिद्धांत दिया- संतुलन, सजगता और समत्व का मार्ग। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे 'धर्मचक्र प्रवर्तन' कहा जाता है। उनके चार आर्य सत्य-दुःख, दुःख का कारण, दुःख का निरोध और दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा-मानव जीवन के गहन विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करते हैं। आज का विश्व युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, असहिष्णुता और मानसिक तनाव से जूझ रहा है। ऐसे समय में बुद्ध का करुणा एवं शांति का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो उठता है। उन्होंने स्पष्ट कहा- 'द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम से ही द्वेष समाप्त होता है।' यह केवल एक नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक शांति का सूत्र है। यदि आज के राष्ट्र, समाज और व्यक्ति इस एक सिद्धांत को आत्मसात कर लें, तो अनेक संघर्षों का समाधान संभव हो सकता है।

महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग उनकी करुणा और क्षमाशीलता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक व्यक्ति जो उन्हें निरंतर अपशब्द कहता था, जब दुर्घटनाग्रस्त होकर पीड़ा में पड़ा, तब बुद्ध स्वयं उसके पास पहुंचे, उसके घावों की सेवा की और अपने भिक्षुओं को उसकी देखभाल का निर्देश दिया। बुद्ध के इस अप्रत्याशित प्रेम और करुणा से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता प्रतिशोध

में नहीं, बल्कि क्षमा और करुणा में निहित है और यही भाव मानवता को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है।

बुद्ध ने केवल बाह्य हिंसा का विरोध नहीं किया, बल्कि मन की हिंसा-ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार को भी सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। हजारों युद्ध जीतने वाला भी उस व्यक्ति के सामने छोटा है, जिसने अपने मन को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने उस समय के समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और लैंगिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान बताया और कहा कि व्यक्ति की श्रेष्ठता जन्म से नहीं, कर्म से निर्धारित होती है। बुद्ध का संघ एक समतामूलक समाज का आदर्श उदाहरण था, जहाँ सभी वर्गों के लोग समान रूप से स्वीकार किए जाते थे। यही कारण है कि उनका आंदोलन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का भी आधार बना। बाद में भीमराव आम्बेडकर ने भी बुद्ध के इसी समतामूलक दृष्टिकोण को अपनाते हुए लाखों लोगों को सामाजिक सम्मान का मार्ग दिखाया। यह दशार्ता है कि बुद्ध का विचार केवल प्राचीन नहीं, बल्कि आधुनिक समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है।

महान करुणामूर्ति बुद्ध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है-'अप्प दीपो भव' अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। यह संदेश व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने, अपने भीतर प्रकाश खोजने और बाहरी सहारों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। बुद्ध का चिंतन हमें भीतर झांकने, मन को निर्मल करने और करुणा, मैत्री, मुदिता एवं उपेक्षा जैसे भावों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। वे बताते हैं कि शांति बाहर नहीं, हमारे अंतर्मन में ही निवास करती है और जब मन जाग्रत होता है, तब अहंकार, क्रोध और हिंसा स्वतः विलीन हो जाते हैं। आज के अशांत और तनावग्रस्त वातावरण में बुद्ध का यह संदेश जन-जन को प्रेम, सह-अस्तित्व और सहिष्णुता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज जब व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों, तकनीकी साधनों और भौतिक सुखों में उलझा हुआ है, तब यह संदेश उसे भीतर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक शांति, संतुलन और आत्मसंतोष केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की सजगता और जागरूकता से प्राप्त होते हैं।

बुद्ध ने वर्तमान में जीने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की चिंताएँ मन को अशांत करती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त करता है। आज के तनावग्रस्त जीवन में 'माइंडफुलनेस' (सचेतनता) की जो अवधारणा विश्वभर में लोकप्रिय हो रही है, उसका मूल स्रोत बुद्ध की ही शिक्षाएँ हैं। यह दशार्ता है कि उनका दर्शन समय से परे है। आज मानवता जिन संकटों से जूझ रही है-पर्यावरणीय असंतुलन, युद्ध, सामाजिक विभाजन, मानसिक अवसाद, उनका समाधान केवल तकनीकी प्रगति से संभव नहीं है। इसके लिए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना आवश्यक है। गौतम बुद्ध का करुणा, अहिंसा, समता और आत्मसंयम का संदेश इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा प्रदान करता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर करुणा का विकास करे, तो समाज में शांति और सौहार्द स्वतः स्थापित हो सकते हैं।

बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहे हैं या केवल उनके उपदेशों का औपचारिक स्मरण कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बुद्ध को केवल पूजें नहीं, बल्कि उन्हें जियें। उनके विचारों को अपने व्यवहार में उतारें। करुणा, प्रेम, सहिष्णुता और समता को अपने जीवन का आधार बनाएं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक 'बुद्ध' को जागृत करेगा, तभी एक शांत, संतुलित और समतामूलक विश्व की स्थापना संभव होगी। यही बुद्ध पूर्णिमा का सच्चा संदेश है और यही मानवता के उज्ज्वल भविष्य की दिशा भी।

नर्स डे: रोगियों की मुस्कान और उम्मीद का दूसरा नाम है नर्स

डॉ. निमित त्यागी

नर्सें भगवान का रूप होती है, वे ही इंसान के जन्म की पहली साक्षी बनती है और उनमें करुणा का बीज बोती है। एक रोगी को स्वस्थ करने में वे अपना सब कुछ दे देती हैं। रोगी की सेवा करते हुए वे अपना पारिवारिक सुख, करियर, जीवन और वर्तमान सबकुछ झोंक देती है।

हर वर्ष 12 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाती है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग सेवा की जननी मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन अनगिनत संवेदनशील हाथों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जो दिन-रात रोगियों के दर्द को कम करने, उन्हें जीवन का भरोसा देने और मृत्यु से संघर्ष कर रहे व्यक्ति के भीतर आशा का दीप जलाने का कार्य करते हैं। दुनिया में नर्सों की सेवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हर दिन, नर्सें शांत शक्ति, स्थिर हाथों और करुणा से भरे दिलों के साथ अस्पतालों, क्लीनिकों और विभिन्न सामुदायिक स्थानों पर कदम रखते हुए रोगियों के लिये देवदूत बनती हैं। नर्सें भगवान का रूप होती है, वे ही इंसान के जन्म की पहली साक्षी बनती है और उनमें करुणा का बीज बोती है। एक रोगी को स्वस्थ करने में वे अपना सब कुछ दे देती हैं। रोगी की सेवा करते हुए वे अपना पारिवारिक सुख, करियर, जीवन और वर्तमान सबकुछ झोंक देती है। वर्ष 2026 की थीम 'हमारी नर्सें, हमारा भविष्य- सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं' पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि यदि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो नर्सों को सम्मान, सुरक्षा, संसाधन और सशक्त वातावरण देना होगा। यह दिवस 1965 से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा शुरू हुआ है, बहुत से लोग इस दिन का उपयोग अपने देश एवं दुनिया में नर्सों द्वारा किए गए अद्भुत सेवा कार्यों का सम्मान करने के लिए करते हैं।

सचमुच नर्सें अस्पतालों की आत्मा होती हैं। चिकित्सक जहां रोग की पहचान और उपचार का मार्ग तय करता है, वहीं नर्स अपने स्पर्श, सेवा, सहानुभूति और निरंतर देखभाल से रोगी को जीने की शक्ति देती है। रोगी जब दर्द, भय, चिंता और असहायता से घिरा होता है, तब नर्स ही उसके चेहरे पर विश्वास की मुस्कान बनकर सामने आती है। वह केवल इंजेक्शन लगाने, दवाइयां देने या रिपोर्ट संभालने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह रोगी के

मनोबल की संरक्षक होती है। वह अपने व्यवहार, शब्दों और संवेदनाओं से रोगी को यह विश्वास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर में नर्सों को 'धरती के फरिश्ते' कहा जाता है। मानवीय सेवा का सबसे जीवंत और प्रभावशाली स्वरूप यदि कहीं दिखाई देता है तो वह नर्सिंग सेवा में दिखाई देता है। एक नर्स रोगी की पीड़ा को केवल देखती नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करती है। वह रात-रात भर जागकर मरीजों की देखभाल करती है, उनके दर्द की भाषा समझती है, उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है और कई बार अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी खुशियों की कीमत पर भी रोगियों की सेवा करती है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के समय पूरी दुनिया ने देखा कि जब लोग अपने ही परिजनों से दूरी बना रहे थे, तब नर्सें संक्रमित मरीजों के सबसे निकट खड़ी थीं। उन्होंने मृत्यु के भय को पीछे छोड़कर जीवन की रक्षा का संकल्प निभाया। उस दौर ने यह सिद्ध कर दिया कि नर्सें केवल स्वास्थ्यकर्मी नहीं, बल्कि

मानवता की सबसे मजबूत प्रहरी हैं। नर्सिंग सेवा केवल पेशा नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और त्याग की साधना है। एक नर्स उस समय भी मुस्कुराती रहती है जब वह स्वयं मानसिक और शारीरिक थकान से गुजर रही होती है। वह रोगियों के बीच आशा का वातावरण बनाती है। कई बार ऐसे मरीज, जो मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं, नर्सों की आत्मीयता और प्रेरणा से पुनः जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान में दवाइयों की अपनी भूमिका है, लेकिन संवेदनशील देखभाल और मानसिक संबल रोगी के उपचार को अधिक प्रभावी बनाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि 'नर्स का स्पर्श भी एक औषधि है।' आज जब दुनिया आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश कर चुकी है, तब भी नर्सिंग सेवा की आवश्यकता और महत्ता कम नहीं हुई, बल्कि और अधिक बढ़ी है। मशीनें रोग का परीक्षण कर सकती हैं, लेकिन वे रोगी की आंखों में छिपे भय को नहीं पढ़ सकतीं। तकनीक इलाज का माध्यम बन सकती है, लेकिन वह करुणा का विकल्प नहीं बन सकती। नर्सों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी संवेदनशीलता है, जो उन्हें अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाओं से अलग पहचान देती है। इसी कारण आज भी नर्सिंग दुनिया का सबसे अधिक अपेक्षित और सम्मानित स्वास्थ्य पेशा माना जाता है।

विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्रशिक्षित नर्सों की कमी है। विकसित देशों में बेहतर वेतन और सुविधाओं के कारण विकासशील देशों की अनेक प्रतिभाशाली नर्सें विदेशों की ओर आकर्षित हो रही हैं। परिणामस्वरूप गरीब और विकासशील देशों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विश्व स्तर पर नर्सों की बढ़ती आवश्यकता यह संकेत देती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता नर्सों की उपलब्धता और दक्षता पर ही निर्भर करेगी। इसलिए यह समय नर्सों को केवल 'सेवक' के रूप में देखने का नहीं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्णायक स्तंभ के रूप में स्वीकार करने का है। भारत जैसे विशाल देश में नर्सिंग सेवा को अधिक सशक्त, सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। नर्सों के लिए बेहतर वेतनमान, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां, पर्याप्त अवकाश, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, कौशल विकास और नेतृत्व के अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिए। निजी और सरकारी अस्पतालों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां नर्सें सम्मान और आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकें। यदि नर्सें स्वयं तनाव, असुरक्षा और उपेक्षा से घिरी रहेंगी, तो स्वास्थ्य सेवाओं की मानवीय गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसलिए नर्सों का कल्याण केवल उनका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, बल्कि पूरी मानवता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की 2026 की थीम भी इसी सोच को आगे बढ़ाती है कि 'सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं।' जब नर्सों को प्रशिक्षण, संसाधन, निर्णय लेने का अधिकार और सामाजिक सम्मान मिलेगा, तभी वे अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज को स्वस्थ बना सकेंगी। यह दिवस हमें केवल नर्सों का सम्मान करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि नर्सों के बिना कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती। अस्पतालों की वास्तविक धड़कन नर्सें ही हैं। रोगियों की आंखों में लौटती चमक, परिवारों के चेहरे पर आती राहत और स्वस्थ जीवन की ओर लौटते कदमों में नर्सों की निःस्वार्थ सेवा का मौन योगदान छिपा होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज नर्सों को केवल एक कर्मचारी के रूप में न देखे, बल्कि उन्हें मानवता के संवेदनशील रक्षकों के रूप में पहचाने। बच्चों के जन्म से लेकर

जीवन की अंतिम सांस तक नर्सें हर महत्वपूर्ण क्षण में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। वे दर्द को कम करती हैं, टूटे मन को संभालती हैं और निराशा में उम्मीद का प्रकाश जगाती हैं। सच तो यह है कि नर्सें केवल शरीर का उपचार नहीं करतीं, वे मनुष्य के भीतर जीने की इच्छा को भी जीवित रखती हैं।

आम दिन हो या महामारियों के खिलाफ जंग, ये नर्स बिना किसी डर के सहजता और उत्साह से अपने कर्तव्य का पालन करती है। इसलिए नहीं कि यह उनका काम है और उसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं बल्कि इसलिए कि वह सबसे पहले दूसरों के स्वस्थ होने और उनकी जान की फिक्र करती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मां के स्वरूप में स्नेहपूर्ण और फिक्र के साथ हर किसी की देखभाल और परवाह करने के शब्द को ही नर्स कहा जाता है। वे अस्पताल की रीड होती है। ऐसी मानवीय सेवा की अद्भूत फरिश्तों के कल्याण एवं प्रोत्साहन का चिन्तन अपेक्षित है। उससे निश्चित ही नर्सों की सेवाएं अधिक सक्षम, प्रभावी एवं मानवीय होकर सामने आयेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर यही संकल्प अपेक्षित है कि हम नर्सों की सेवाओं को अधिक सम्मान, सुरक्षा और सहयोग प्रदान करें। उनके कल्याण, प्रोत्साहन और सशक्तिकरण का व्यापक चिंतन हो। जब नर्सों का जीवन अधिक सुरक्षित, संतुलित और सम्मानपूर्ण होगा, तब उनकी सेवाएं और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और मानवीय बन सकेंगी। यही इस दिवस का वास्तविक उद्देश्य और मानवता के प्रति हमारी सच्ची संवेदनशीलता होगी।

अब कमजोर मानसून व अल नीनो का जोखिम

हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2026 में कमजोर मानसून से भारत में कृषि की पैदावार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढने और विकास दर में कमी की चुनौती होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों 13 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग ने अल नीनो के कारण 2026 में सामान्य से कम मॉनसून का अनुमान लगाया है। यह पूवार्नुमान पिछले 26 वर्षों में मानसून का सबसे कम शुरूआती अनुमान है। इससे देश में कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बारिश के दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 92 प्रतिशत रहने की संभावना बताई है। यह पूवार्नुमान 5 फीसदी अधिक या कम की मॉडल त्रुटि के साथ जारी किया गया है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट में भी इसी तरह का पूवार्नुमान जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 75

मनोज शर्मा

प्रतिशत वर्षा पर आधारित मॉनसून सीजन (जून से सितंबर) में 5 प्रतिशत कम या ज्यादा के साथ 94 प्रतिशत वर्षा हो सकती है। यद्यपि पिछले आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम मॉनसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, वितरण और फैलाव लगभग समान रहा, तब खरीफ के उत्पादन में अधिक कमी नहीं हुई, किन्तु गैर-सिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए जोखिम हो सकती हैं। साथ ही दलहन और तिलहन का कम उत्पादन खाद्य महंगाई पर असर डाल सकता है। एक ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया संघर्ष से महंगे उर्वरक, महंगे तेल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से खेती की लागत बढ़ी है, तब कमजोर मानसून से न केवल किसानों और कृषि पर, वरन आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हो सकता है। साथ ही पेयजल समस्या की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में किसानों व कृषि क्षेत्र के समक्ष दिखाई दे रही आसन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुआयामी रणनीति जरूरी है। गौरतलब है कि नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 फीसदी सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मॉनसून पर निर्भर है। कम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स (सीडब्ल्यूएमआई) के अनुसार लगभग 74 प्रतिशत गेहूं और 65 प्रतिशत चावल की खेती वाले क्षेत्र पहले से ही भारी जल संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते रुझान से भारत में मॉनसून की वर्षा पर निर्भरता बढ़ी हुई है। अब अल नीनो के खतरे और कमजोर मॉनसून

की आशंका से जलाशय के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश में कुल 183.565 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) क्षमता वाले 166 प्रमुख जलाशयों के भंडारण पर नजर रखता है। सीडब्ल्यूसी का कहना है कि इस समय इन जलाशयों में कुल क्षमता का 44.71 प्रतिशत है। हाल के महीनों में इसमें तेजी से कमी आई है। प्राकृतिक पुनर्भरण प्रणाली कमजोर होने से भी हालात बिगड़ रहे हैं। वस्तुतः जलाशयों में पर्याप्त पानी 2025 के मॉनसून सीजन में अच्छी बारिश के कारण है, लेकिन अब इस साल कमजोर मॉनसून की आशंका से पानी का संग्रहित स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है। वास्तव में देश के किसानों और कृषि क्षेत्र की चिंताएं बढ़ाने वाला यह परिदृश्य देश के वर्तमान सुकूनदायक कृषि क्षेत्र के समक्ष एक चुनौती बनकर दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2024-25 में भारत में 35.70 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इस वर्ष 2025-26 में इससे भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। 2026 में गेहूं की खेती का रकबा भी पिछले वर्ष के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढकर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है और एक और अच्छी फसल की संभावना का संकेत देता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में एक मई 2026 को लगभग गेहूं और चावल का 600 लाख टन से अधिक का उपलब्ध स्टॉक खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत की मजबूती है। इस समय देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रकाशित निर्यात आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 55 अरब डॉलर मूल्य का कृषि निर्यात किया है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कृषि निर्यात के लिए देश के कृषि निर्यात परिदृश्य पर यह उभकर दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चार गुना, फलों और दालों का निर्यात तीन गुना, खाद्यान्न का निर्यात दो गुना और चावल के निर्यात में करीब 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इतना ही नहीं पिछले करीब चार साल तक निर्यात पर नियंत्रण रखने के बाद भारत ने एक बार फिर मई 2026 से गेहूं के वैश्विक बाजार में वापसी का बड़ा संकेत दिया है। भारत सरकार ने घरेलू बाजारों को स्थिर करने और उत्पादकों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक और किसान-केंद्रित कदम उठाते हुए 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और अतिरिक्त 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। मिस्त्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार और अफ्रीका के कई देश भारतीय गेहूं में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष सामान्य से कम मानसून और खेती की बढ़ती लागत के मद्देनजर कई बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। यद्यपि अभी निर्धारित गेहूं के निर्यात आदेशों की पूर्ति अवश्य की जाए, लेकिन आगामी निर्यात आदेशों की पूर्ति के लिए सजगता रखी जाए। देश ने देखा है कि वर्ष 2021-22 में 70 लाख टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया था, लेकिन वर्ष 2024 में गेहूं का आयात करना पड़ा। इस बात पर ध्यान देना होगा कि कम बारिश से जलाशयों में पानी का स्तर गिरने से सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, ऐसे में अभी से जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए। कृषि उत्पादन घटने की आशंका से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय जो खुदरा महंगाई दर 3.40 प्रतिशत है, उसके बढने की आशंका होगी। अतएव मूल्यों की रोकथाम की रणनीति के साथ आगे बढना होगा। अब कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देने और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जाना होगा। व्यापक भंडारण अभियान और कृषि-वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति शृंखलाओं में नवाचार को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे।

चूंकि देश के विभिन्न हिस्सों में विविध जलवायु है और कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों के मामले में वह समृद्ध है, अतएव ऐसे में भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढना होगा। चूंकि देश में अभी भी अनाज, दाल तथा तिलहन के उत्पादन का स्तर मौसम पर ही निर्भर होता है, ऐसे में क्षेत्रवार और फसलवार आधार का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई व्यवस्था की नई नीति तैयार करना लाभप्रद होगी। अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में वर्ष 2028 तक सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाना होगा। उम्मीद करें कि ऐसे प्रयासों से इस वर्ष 2026 में किसानों और कृषि क्षेत्र को मुश्किलों से बचाते हुए आम आदमी व अर्थव्यवस्था की चिंताएं भी कम की जा सकेंगी।

वट सावित्री व्रत: नारी शक्ति, निष्ठा और जीवन-संकल्प का पर्व

वट सावित्री व्रत भारतीय नारी की आस्था, निष्ठा और जीवन-संकल्प का प्रतीक है

अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला यह व्रत सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा है– जहाँ नारी की दृढ़ता ने मृत्यु को भी पराजित किया।

वट सावित्री व्रत की कथा सती सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की पौराणिक कहानी है। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता, पतिव्रता धर्म और वटवृक्ष (बरगद) के नीचे कठोर तप से सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है।

वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा

- **सावित्री का विवाह :** मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने राजा द्युमत्सेन के वनवासी पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को बता दिया था कि सत्यवान की आयु केवल एक वर्ष शेष है, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया।
- **मृत्यु का दिन :** जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। वहां एक बरगद (वट) वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण निकलने लगे। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने पहुंचे।
- **यमराज से संवाद :** सावित्री ने यमराज के पीछे-पीछे चलना शुरू कर दिया। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए यमराज से अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगी।
- **वरदान की प्राप्ति :** सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने उन्हें कई वरदान दिए, जिसमें सास-ससुर की आंखें ठीक होना और उनका राज्य वापस मिलना शामिल था। अंतिम वरदान में सावित्री ने यमराज से स्वयं के लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा, जो उन्हें अनजाने में देना पड़ा।
- **पति को जीवनदान :** जब यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया, तो सावित्री ने कहा कि यह वरदान पति के बिना कैसे पूरा होगा? तब यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े।
- **वटवृक्ष का महत्व :** सावित्री ने उसी वटवृक्ष के नीचे अपने पति को पुनः जीवित पाया। वटवृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस पूजा में वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजा का विशेष महत्व है।
- **व्रत का महत्व:** यह व्रत वैवाहिक जीवन की

वट सावित्री व्रत (बड़-मावस)

- **तिथि : ज्येष्ठ अमावस्या**
- **कथा : सावित्री-सत्यवान**
- **प्रतीक : वट वृक्ष**

बाधाओं को दूर करता है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं।

- **पूजा विधि (संक्षेप में) :** महिलाएं सुबह स्नान कर सोलह श्रृंगार करती हैं और वट वृक्ष (बरगद) के नीचे सावित्री-सत्यवान की पूजा करती हैं। वृक्ष पर कच्चा सूत (कलावा) लपेटते हुए 108 परिक्रमा की जाती है।

सावित्री कथा का प्रतीक

सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस प्राप्त किया
यह कथा नारी शक्ति का प्रतीक है।

वट वृक्ष का महत्व

वट वृक्ष दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक है इसकी पूजा जीवन की स्थिरता का संकेत है।

सांस्कृतिक अर्थ

यह व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि परिवार और संबंधों की स्थिरता का प्रतीक है।

समकालीन महत्व

आज यह पर्व नारी शक्ति और आत्मबल का प्रतीक बन गया है।

निष्कर्ष

व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और संकल्प जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं।

कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते समय ना करें ये गलतियां, बिगड़ जाएगा पूरा लुक

कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते समय उसकी मात्रा का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आप बार-बार पाउडर लगाती हैं या फिर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हैं तो इससे फेस केकी महसूस होता है। साथ ही, फोटोज में मेकअप खराब लगने लगता है। इसलिए, कोशिश करें कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर को टी-जोन पर फोकस करके अप्लाई करें।

मेकअप करते समय हम सभी कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल जरूर करती हैं। यह हम सभी की मेकअप किट का हिस्सा होता ही है। चाहे मेकअप का टचअप करना हो या फिर इंस्टेंट फ्रेश लुक चाहिए, कॉम्पैक्ट पाउडर बेहद ही काम आता है। इसे इस्तेमाल करना बेहद ही आसान लगता है। लेकिन वास्तव में इसे इस्तेमाल करना उतना भी आसान नहीं है, जितना हम सभी समझते हैं। अगर कॉम्पैक्ट पाउडर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे मेकअप डल लगने से लेकर केकी मेकअप तक की कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। जिससे आपका चेहरा काफी अजीब नजर आ सकता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही कॉम्पैक्ट पाउडर से जुड़ी गलतियों के बारे में बता रहे हैं, जो आपका पूरा लुक खराब कर सकती हैं-

गलत शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल करना

मार्केट में कई शेड में कॉम्पैक्ट पाउडर मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किन टोन से ज्यादा गोरा या ज्यादा डार्क शेड इस्तेमाल करती हैं, तो यह आपके लुक को बिगाड़ सकता है। इससे आपका चेहरा अजीब सा लगने लगता है। इतना ही नहीं, गर्दन और चेहरे का कलर भी मिसमैच हो जाता है, जिससे पूरा मेकअप ही नकली महसूस होता है। आपसे कॉम्पैक्ट पाउडर चुनते समय गलती ना हो, इसलिए उसे अपनी जॉलाइन पर टेस्ट करें।

जरूरत से ज्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल करना

कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते समय उसकी मात्रा का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आप बार-बार पाउडर लगाती हैं या फिर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हैं तो इससे फेस केकी महसूस होता है। साथ ही, फोटोज में मेकअप खराब लगने लगता है। इसलिए, कोशिश करें कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर को टी-जोन पर फोकस करके अप्लाई करें।

कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते समय गलत टूल का इस्तेमाल करना

कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते समय आप किस टूल का इस्तेमाल कर रही हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। अगर आप गंदे पफ का इस्तेमाल करती हैं या फिर गलत ब्रश से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हैं तो इससे पाउडर सही तरह से ब्लेंड नहीं होता है। साथ ही, मेकअप पैची लगता है और अनइवन फिनिश आती है।

रूखी स्किन पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना

कुछ लोग अपनी रूखी स्किन पर ही कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप बिना मॉइश्चराइज के पाउडर इस्तेमाल करती हैं तो इससे स्किन फ्लेकी और पैची नजर आने लगती है। इतना ही नहीं, रूखी स्किन पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से फाइन लाइन्स और रिंकल्स और भी ज्यादा दिखने लगते हैं, जिससे फेस डल नजर आता है। इसलिए, हमेशा पहले मॉइश्चराइजर व हल्का प्राइमर लगाएं और उसके बाद ही कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करें।

फलों के छिलकों से बढ़ाएं अपने स्किन की ब्यूटी

जमाने में हर किसी की यह चाहत होती है कि वह सुंदर दिखें। इसके लिए महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यह सभी प्रोडक्ट स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। आप नेचुरल रूप से ग्लोइंग स्किन पा सकती हैं। फलों का सेवन हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है।

वहीं फलों के छिलके भी काफी फायदेमंद होते हैं। फलों के छिलके त्वचा पर लगाने से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं और हमारी स्किन भी ग्लो करने लगती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए आपको उन फलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके छिलके आप अपनी स्किन पर लगा सकती हैं।

केले के छिलके

केले के छिलके में विटामिन ए, बी और विटामिन सी पाया जाता है। केले के छिलके को त्वचा पर लगाने से यह नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे के दाग-धब्बे दूर होते हैं।

पपीते के छिलके

पपीते के छिलके में पेपिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जोकि हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है। इसको आप अपनी त्वता पर सीधे तौर पर अप्लाई कर सकते हैं।

संतरे के छिलके

संतरे में विटामिन सी और नेचुरल ऑयल पाया जाता है। इसकी वजह से इसको अच्छा एक्सफोलिएटर माना जाता है। संतरे कि छिलके के इस्तेमाल से डार्क स्पॉट्स और एक्ने से निजात मिल सकती है। यह कोलेजन बनाने में भी मदद करता है। संतरे के छिलके को धूप में सुखाकर पेस्ट बना लें। फिर इसमें दही मिलाकर इसको फेस पर अप्लाई करें। इससे आपकी त्वचा चांद जैसी चमकने लगेगी।

नींबू के छिलके

बता दें कि नींबू के छिलके में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इससे स्किन पर ग्लो आता है और नींबू के छिलकों को सुखाकर इसका पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर में शहद डालकर इसको मास्क की तरह फेस पर अप्लाई करें। इससे स्किन में ग्लो आएगा और बाकी समस्याएं भी दूर होने लगेंगी।

कीवी के छिलके

कीवी के छिलकों में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कीवी के छिलकों को दही में मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर पेस्ट को फेस पर अप्लाई करें, इससे स्किन ब्राइटनेस बढ़ती है।

हिमालय नहीं, साउथ इंडिया की इन 3 चोटियों पर मिलता है जन्नत का एहसास

अरुण मिश्रा

घूमने-फिरने का शौक तो सभी को होता है। जैसे ही कोई मौका आता है, लोग बैग उठाकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। किसी को पहाड़ों पर जाना पसंद होता है, तो कोई बीच पर सुकून भरे पल बिताने जाता है। घूमने से हमारे मन को शांति मिलती है।

वहीं भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां का नजारा देखने लायक होता है। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, वह ट्रेकिंग जरूर करते हैं। जब भारत की सबसे खूबसूरत चोटियों की बात होती है, तो लोगों के मन में सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का ख्याल आता है। हालांकि यह दोनों ही राज्य बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी चोटियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां की ट्रेकिंग आपको एक बार जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपको जीते जी स्वर्ग के दर्शन करना चाहते हैं, तो यहां जरूर आएं।

कलसूबाई पीक, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की खूबसूरती से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। नासिक जिले में स्थित कलसूबाई पीक दुनिया की सबसे खूबसूरत पीक में से एक है। यह करीब 5400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ट्रेकिंग बरी के बेस गांव से शुरू होती है। जहां पर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां से एडवेंचर ट्रेक करके पहुंचा जा सकता है। जब आप इसकी पीक पर पहुंचेंगी, तो वहां पर आपको बेहद खूबसूरत और दिल थाम देने वाले नजारे देखने को मिलेंगे।

नेत्रावती पीक, कर्नाटक

नेत्रावती पीक कर्नाटक राज्य की सबसे खूबसूरत चोटी है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको करीब 6 किमी की ट्रेकिंग करनी पड़ेगी। वहीं आपको ट्रेकिंग के दौरान पहाड़ों पर हरे-भरे नजारे देखने को मिलेंगे, वहीं जब आप टॉप पर पहुंचेंगे, तो आपको दिल थाम देने वाला नजारा देखने को मिलेगा।

कोलुक्कुमलाई पीक, तमिलनाडु

भले ही यह पीक तमिलनाडु है, लेकिन इसकी ट्रेकिंग की शुरूआत केरल के इडुक्कि जिले से होती है। यहां का सनराइज देखने का लायक होता है। अगर आप यहां पर सूर्योदय का खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं, तो आपको सुबह 3 बजे निकलना होगा।

धर्मशाला और मैक्लोडगंज: तिब्बती संस्कृति और हिमालयी सौंदर्य का अद्भुत संगम

धर्मशाला से लगभग 10 किमी दूर स्थित मैक्लोडगंज तिब्बती संस्कृति और बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र है। यह छोटा सा कस्बा विदेशी पर्यटकों, ध्यान-साधकों, योगाभ्यासियों और पर्वतारोहण प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला और मैक्लोडगंज उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं। ये स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि तिब्बती संस्कृति, बौद्ध धर्म और अध्यात्मिकता के प्रमुख केंद्र भी हैं। धर्मशाला को 'छोटा ल्हासा' भी कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बती शरणार्थियों का प्रमुख निवास स्थान है।

धर्मशाला: शांत वादियों में बसा आध्यात्मिक केंद्र

धर्मशाला दो भागों में बँटा हुआ है – अपर धर्मशाला (मैक्लोडगंज) और लोअर धर्मशाला। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना बना रहता है और यहाँ की हरियाली, ऊँची पहाड़ियाँ, देवदार और चीड़ के वृक्ष इसे स्वर्ग जैसा अनुभव देते हैं।

प्रमुख आकर्षण:

HPCA क्रिकेट स्टेडियम: समुद्र तल से लगभग 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्टेडियम दुनिया के सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है।

कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम: यहाँ आप पहाड़ी चित्रकला, तिब्बती और बौद्ध वस्तुओं का संग्रह देख सकते हैं।

त्सुगलाखांग कॉम्प्लेक्स: यह दलाई लामा का निवास और आधिकारिक मठ है, जहाँ लोग बौद्ध धर्म और ध्यान की गहराइयों को अनुभव कर सकते हैं।

मैक्लोडगंज: तिब्बती जीवनशैली और प्रकृति का संगम

धर्मशाला से लगभग 10 किमी दूर स्थित मैक्लोडगंज तिब्बती संस्कृति और बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र है। यह छोटा सा कस्बा विदेशी पर्यटकों, ध्यान-साधकों, योगाभ्यासियों और पर्वतारोहण प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

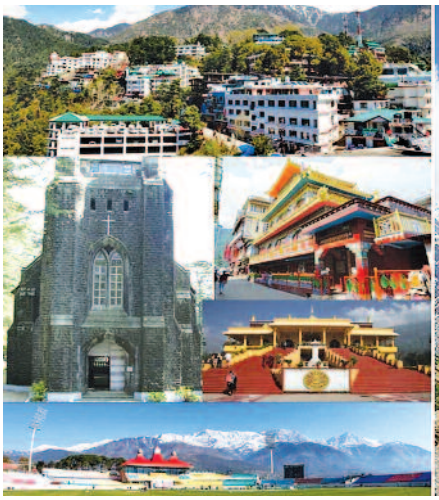

प्रमुख आकर्षण:

नामग्याल मठ: यह दलाई लामा का निजी मठ है और ध्यान-प्रेमियों के लिए विशेष स्थान है।

भागसूनाग मंदिर और झरना: यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पास ही स्थित झरना एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है।

त्रियुंड ट्रेक: यह एक मध्यम स्तर का ट्रेक है जहाँ से धौलाधार की पर्वतमालाएँ बेहद निकट से दिखती हैं। यह ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है।

तिब्बतन मार्केट: यहाँ से आप तिब्बती हस्तशिल्प, थंका पेंटिंग, ऊनी कपड़े और बुद्ध प्रतिमाएँ खरीद सकते हैं।

क्या करें धर्मशाला और मैक्लोडगंज में?

- ध्यान और योग शिविरों में भाग लें
- बौद्ध धर्म पर आधारित वर्कशॉप
- स्थानीय तिब्बती भोजन का आनंद लें (मोमो, थुकपा आदि)
- ट्रेकिंग, कैम्पिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियाँ
- स्थानीय भिक्षुओं से बातचीत और बौद्ध संस्कृति को समझना

यात्रा का उत्तम समय

मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का समय यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त है। सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए दिसंबर-जनवरी का समय भी लोकप्रिय है।

कैसे पहुँचे?

हवाई मार्ग: निकटतम हवाई अड्डा गग्गल (धर्मशाला) है, जो शहर से लगभग 13 किमी दूर है।

रेल मार्ग: सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जहाँ से टैक्सी या बस द्वारा धर्मशाला पहुँचा जा सकता है।

सड़क मार्ग: दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

धर्मशाला और मैक्लोडगंज केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के संगम स्थल हैं। यदि आप जीवन की दौड़-भाग से कुछ समय निकालकर प्रकृति और आत्मा के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो यह स्थल आपके लिए एक आदर्श गंतव्य है।

बच्चों को चाय-बिस्कुट देना खतरनाक एनीमिया समेत 5 बीमारियों का खतरा

कई घरों में सुबह की शुरूआत आमतौर पर चाय और बिस्कुट या हल्के स्नैक्स से होती है। जब घर के बड़े ऐसा करते हैं, तो बच्चे भी यही आदत अपना लेते हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक यह आदत बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। चाय और बिस्कुट से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। वहीं लंबे समय तक ऐसा नाश्ता करने से बच्चे के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

वहीं बच्चे की इम्युनिटी भी कमजोर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि बच्चे को हेल्दी नाश्ते का ऑप्शन दिया जाए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि चाय और बिस्कुट बच्चे के लिए अनहेल्दी क्यों है। साथ ही यह बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कैसे बुरा असर डाल सकता है।

डॉ. मुकुल शर्मा

चाय-बिस्किट क्यों है अनहेल्दी

सुबह का नाश्ता बच्चे के पूरे दिन की एनर्जी, ओवरऑल हेल्थ और दिमाग के काम के लिए बहुत जरूरी है। चाय-बिस्कुट में न के बराबर पोषण होता है। बिस्कुट ज्यादातर चीनी, मैदा और अनहेल्दी फैट से बना होता है। इनमें फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन जैसे पोषक तत्व न के बराबर पाए जाते हैं। वहीं चाय में भी कोई खास पोषण नहीं होता है। चाय और बिस्कुट मिलकर 'खाली कैलोरी' देते हैं। जोकि पेट तो भरते हैं, लेकिन शरीर को जरूरी पोषण और ताकत नहीं देते हैं। इसी वजह से यह कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए पूरी तरह से अनहेल्दी है।

एनीमिया का खतरा

चाय में टैनिन नामक तत्व पाया जाता है। जोकि शरीर में आयरन को सही तरीके से अवशोषित होने से रोकता है। अगर रोज सुबह बच्चा चाय पीता है, तो उनके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। जोकि आगे चलकर एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। इससे बच्चे की इम्युनिटी और ग्रोथ दोनों पर निगेटिव असर पड़ सकता है।

बढ़ सकता है चिड़चिड़ापन

बिस्कुट में चीनी अधिक होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक से गिर जाता है। इस उतार-चढ़ाव के कारण बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं। बच्चे का ध्यान कम लगने

की शिकायत भी हो सकती है। वहीं बच्चे का बार-बार कुछ अनहेल्दी खाने की इच्छा हो सकती है।

नींद पर असर

बच्चों के लिए कैफीन वाली चाय सही नहीं होती है। यह उनकी नींद को खराब कर सकती है और बेचैनी को बढ़ा सकती है। इससे बच्चे की ध्यान लगाने की क्षमता और व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है।

अनहेल्दी खाने की इच्छा

चाय-बिस्कुट का कॉम्बिनेशन शरीर को ज्यादा देर तक एनर्जी नहीं देता है। थोड़ी देर में बच्चा फिर भूख महसूस करने लगता है। जिससे वह ज्यादा खाना खा सकते हैं। या फिर बार-बार अनहेल्दी स्नैक्स मांग सकते हैं।

कमजोर इम्युनिटी

हर रोज चाय-बिस्कुट खाने से बच्चे के शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। जिससे बच्चे के विकास पर असर पड़ता है। ऐसी आदत की वजह से बच्चे जल्दी थक जाते हैं और उनकी इम्युनिटी कमजोर हो सकती है। शरीर में पोषक तत्वों खासकर कैल्शियम और आयरन की कमी हो सकती है।

मोटापे की समस्या

ज्यादा चीनी या तला भुना नाश्ता देने से बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है। वहीं बच्चे को दांत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

कमजोर हो सकती है याददाश्त

पोषण की कमी वाला नाश्ता बच्चे के दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है। बच्चे को कॉन्स्ट्रेशन में समस्या होती है। याददाश्त कमजोर हो सकती है और शिक्षा के प्रदर्शन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।

जानिए कैसे छुड़ाएं यह आदत

माता-पिता को ध्यान रखना चाहिए कि आदत एकदम से नहीं छूटती है। इसलिए धीरे-धीरे चाय-बिस्कुट की जगह फल, दूध या हेल्दी नाश्ता देना शुरू करें। बच्चे वही सीखते हैं, जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं।

जब आप हेल्दी नाश्ता करेंगे, तो उसी आदत को बच्चा भी अपनाएगा। अलग-अलग शेप और अच्छे तरीके से रंग-बिरंगे फलों को सजाकर खाना दें। जो बच्चे को पसंद आए। रोजाना एक ही समय पर नाश्ता करने की आदत डालें। इससे बच्चे की आदत पड़ जाएगी।

बच्चों को आसान भाषा में यह बताएं कि अच्छा खाना उनके शरीर को ताकत देता है और सीखने व खेलने में मदद करता है।

पेरेंट्स को समझना जरूरी

बता दें कि पेरेंट्स को यह समझना जरूरी हो जाता है कि चाय-बिस्कुट बच्चे को पोषण पूरा नहीं देते हैं। इससे बच्चे के दिमाग और शरीर पर निगेटिव असर पड़ सकता है।

इसलिए बच्चे को हमेशा ऐसा नाश्ता देना चाहिए, जो पोषक तत्वों से भरपूर और संतुलित हो। क्योंकि पोषण से भरपूर नाश्ता बच्चों को पूरा दिन के लिए एनर्जी देता है और पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी मदद करता है।

हेल्दी नाश्ते के ऑप्शन

- सांभर और नारियल की चटनी के साथ इडली
- दही के साथ होल व्हीट वेजिटेबल पराठा
- दूध के साथ पीनट बटर या पनीर सैंडविच
- होल ग्रेन टोस्ट के साथ उबले अंडे
- दूध और फलों के साथ ओट्स दलिया
- मेवे और बीजों के साथ फ्रूट स्मूदी
- पनीर स्टफिंग वाला बेसन चिल्ला
- मूंगफली के साथ वेजिटेबल पोहा
- सब्जियों के साथ उपमा
- सादा या मीठा दलिया

सामंथा रुथ: मॉडलिंग से टॉप एक्ट्रेस बनने तक, उतार-चढ़ाव भरा रहा फिल्मी सफर

दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली है।

दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपना 39वां जन्मदिन मनाया। एक्ट्रेस ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली है। सामंथा रुथ प्रभु ने हर किरदार को बड़े शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा है और अपने फैंस का दिल जीता है। सामंथा रुथ की इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं के साथ पर्दे पर सफल जोड़ी बना चुकी हैं। हालांकि सामंथा की पर्सनल लाइफ उतार-चढ़ाव भरी रही है। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

चेन्नई में 28 अप्रैल 1987 को सामंथा रुथ प्रभु का जन्म हुआ था। उनका बचपन चेन्नई में बीता था और फिर उन्होंने कम उम्र में मॉडलिंग करना शुरूकर दिया था। सामंथा रुथ प्रभु के पिता का नाम जोसेफ प्रभु थे, जोकि तेलुगू से थे और उनकी मां का नमा निनेती प्रभु मलयाली थीं। वहीं सामंथा ने बाद में नागा चैतन्य संग गोवा में हिंदू और ईसाई परंपरा के मुताबिक शादी की थी। लेकिन बाद में सामंथा और नागा चैतन्य का तलाक हो गया।

फिल्मी करियर

साल 2010 में 'या या माया चेस्वे' से सामंथा ने मॉडलिंग से एक्टिंग करियर की शुरूआत की थी। इसके बाद वह साल में तीन से चार फिल्मों में काम करने लगीं। एक सफल और बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ ही सामंथा रुथ प्रभु फैशन डीवा भी हैं। जिनके स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस फैंस को बेहद पसंद आते हैं। सामंथा ने तमिल, मलयालम और तेलुगु में सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। साल 2013 में एक्ट्रेस को तेलुगु और तमिल दोनों इंडस्ट्री में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी मिला था। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु दक्षिण भारतीय सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। वहीं सालाना तीन करोड़ रुपए की कमाई करने वाले सामंथा ने फिल्म पुष्पा में 3 मिनट के गाने के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इसके अलावा एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट और मॉडलिंग से भी मोटी कमाई करती हैं।

हॉट महिलाओं की फेहरिस्त में जगह पा चुकी हैं वर्तिका सिंह

पिछले साल 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' (2025) को ऑडियंस और क्रीटिक्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म में यामी गौतम 'शाह बानो' और इमरान हाशमी उनके पति 'मोहम्मद अहमद खान' की भूमिका में दिखाई दिए जबकि एक्ट्रेस वर्तिका सिंह भावनात्मक रूप से मजबूत 'मोहम्मद अहमद खान' की दूसरी बीवी के किरदार में थीं। इस किरदार में वर्तिका सिंह के काम को हर किसी ने खूब पसंद किया। इसके बाद वह अचानक सुर्खियों में आ गई।

फिल्म में वर्तिका सिंह की एक्टिंग को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। सोशल मीडिया यूजर्स तो उनकी तारीफ करते थक ही नहीं रहे थे। सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए वर्तिका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म 'हक' (2025) तक पहुंचने का वर्तिका सिंह का सफर आसान नहीं रहा। यह फिल्म उन्हें कई ऑडिशन मे मिले रिजेक्शन के बाद मिली थी। अनेक ऑडिशन अच्छे होने के बावजूद जब रोल किसी और को ही मिले, तब वर्तिका ने घर लौटने तक का सोच लिया था लेकिन फिर मॉडलिंग में अच्छे मौके मिलने लगे और वह मुंबई में टिकी रहीं।

27 अगस्त 1993 को लखनऊ में पैदा हुई मॉडल-एक्ट्रेस वर्तिका सिंह के पिता ब्रज नाथ सिंह खेती से जुड़े वैज्ञानिक जबकि मां वहां के एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं।

वर्तिका सिंह की शिक्षा लखनऊ के कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल में हुई। उन्होंने इसाबेला थोबर्न कॉलेज से क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में बेचलर और लखनऊ विश्वविद्यालय से सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। साल 2015 में 'फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल' का खिताब हासिल कर चुकी वर्तिका सिंह को 'जीक्यू मेगजीन' ने साल 2016 में भारत की सबसे हॉट महिलाओं की फेहरिस्त में स्थान दिया था। उसके बाद वर्तिका सिंह ने साल 2017 में 'किंगफिशर मॉडल हंट प्रतियोगिता' में भाग लिया और 'किंगफिशर बिकिनी कैलेंडर' के मार्च और अक्टूबर वाले पन्नों पर जगह बनाई।

साल 2019 में वर्तिका सिंह को मिस यूनिवर्स इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष 20 में स्थान बनाया। फिल्मों में आने के पहले वर्तिका सिंह ने बतौर प्रोफेशनल मॉडल खास पहचान बनाते हुए अलग मुकाम हासिल किया। कुणाल खेमू के साथ 'सवारे...' (2017) और ऐश किंग और करन के म्यूजिक वीडियो 'किशमिश...' (2019) कर चुकी वर्तिका सिंह का आज फैशन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर काफी नाम है। खासकर इंस्टाग्राम पर वह अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरती हैं।

ग्लोबल बनीं 'नोरा फतेही'

फीफा विश्व कप 2026 में परफॉर्मेंस से मचाएंगी धमाल

नोरा फतेही 12 जून, 2026 को टोरंटो, कनाडा के बीएमओ फील्ड में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी और गाएंगी, जो उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। उनकी भागीदारी विश्व के सबसे बड़े खेल और मनोरंजन मंचों में से एक पर उनकी बढ़ती उपस्थिति को और मजबूत करती है। फीफा की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नोरा उन वैश्विक कलाकारों में शामिल होंगी जिनमें एलनिस मॉरिसेट, एलेशिया कारा, इलियाना, जेसी रेयेज, माइकल बुबले, संजॉय, वेजड्रीम और विलियम प्रिंस शामिल हैं।

अमेरिका के उद्घाटन समारोह में अनीता, फ्यूचर, कैटी पेरी, लिसा, रेमा और टाइला जैसे कलाकार प्रस्तुति देंगे, जो अंतरराष्ट्रीय संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का एक विविध प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो द्वारा साझा की गई एक पोस्ट में कार्यक्रम के संगीत कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। नोरा फतेही की इस प्रस्तुति से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता और विभिन्न संस्कृतियों में उनकी गहरी पकड़ का पता चलता है। 2022 में फीफा विश्व कप समारोह के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के बाद, उनकी वापसी संगीत, नृत्य और मंच पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण एक बहुमुखी कलाकार के रूप में उनकी बढ़ती मांग को रेखांकित करती है। यह अवसर नोरा की गायिका और कलाकार दोनों की दोहरी भूमिका के लिए उल्लेखनीय है, जो एक बहुमुखी वैश्विक मनोरंजनकर्ता के रूप में उनकी पहचान को और मजबूत करता है। अपने पूरे करियर के दौरान, नोरा फतेही ने अंतरराष्ट्रीय मंचों और प्रमुख खेल आयोजनों से मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, जिनमें टी20 विश्व कप से संबंधित प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। प्रत्येक प्रदर्शन ने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम एक गतिशील कलाकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन समारोह में उनकी आगामी प्रस्तुति उनके वैश्विक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने की उम्मीद है। टोरंटो में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त कलाकारों के साथ मंच साझा करते हुए, उनसे विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक में अपनी विशिष्ट ऊर्जा, संगीत और प्रभावशाली प्रस्तुति देने की उम्मीद है। इस आयोजन के अलावा, नोरा फतेही हनी सिंह के साथ अपने आई-पॉप सिंगल 'बॉडी रोल' को शनिवार को रिलीज करने की तैयारी में हैं। इस गाने की वैश्विक लोकप्रियता को लेकर काफी उत्सुकता है।

खेल मंत्रालय का बड़ा दांव

स्टार एथलीट नीरज चौपड़ा और मनू भास्कर विदेश में करेंगे स्पेशल ट्रेनिंग

खेल मंत्रालय ने आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए नीरज चोपड़ा और मनु भाकर के विदेशी प्रशिक्षण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। पीठ की चोट से उबर रहे स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग करेंगे, जबकि निशानेबाज मनु भाकर एशियाई खेलों की तैयारी के लिए इटली में प्रशिक्षण लेंगी।

पीठ की चोट से उबर रहे भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 25 मई से स्विट्जरलैंड के ओलंपिक ट्रेनिंग केंद्र में जाएंगे जबकि निशानेबाज मनु भाकर ट्रेनिंग के लिए

इटली चली गईं। खेल मंत्रालय ने इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों को देखते हुए विदेशों में ट्रेनिंग के इनके प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। नीरज के दोनों प्रतियोगिताओं में खेलने की उम्मीद है जबकि मनु सिर्फ एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगी क्योंकि निशानेबाजी राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है।

मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) ने यहां अपनी 173वीं बैठक में नीरज के स्विट्जरलैंड के बीन में 47 दिन के ऑफ सत्र ट्रेनिंग शिविर के आग्रह के अलावा मनु के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने बयान में कहा, ''तुर्किये में पीठ की चोट के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के कोर खिलाड़ी दो बड़ी बहु खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए 25 मई से 10 जुलाई तक बीन के ओलंपिक ट्रेनिंग केंद्र में ट्रेनिंग करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई से दो अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में किया जाएगा जबकि एशियाई खेल 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक जापान के आइची-नगोया में होंगे।

नीरज ने इस साल अभी तक किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है क्योंकि उनका पहले से तय सत्र का पहला टूर्नामेंट दोहा डाइमंड लीग खाड़ी क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण स्थगित हो गया था। नीरज ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और 2018 तथा 2022 एशियाई खेलों में भी शीर्ष पर रहे थे। हरियाणा के 28 साल के इस खिलाड़ी के साथ उनके फिजियोथेरेपिस्ट इशान मारवाहा और कोच जय चौधरी भी बीन में होंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां वह तोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर सुपरस्टार बनने से पहले लंबे समय तक रहे हैं।

साइ ने कहा, ''इस प्रस्ताव में तीन लोगों की टीम के आने-जाने और रहने का खर्च शामिल है जिसमें हवाई किराया, होटल का खर्च, खाना, वीजा, भाले और ट्रीटमेंट बेड के लिए अतिरिक्त बैगेज भत्ता, मेडिकल बीमा और 47 दिन के लिए हर दिन 25 डॉलर का भत्ता वगैरह शामिल हैं।'' खेल सचिव हरि रंजन राव की अगुआई वाले एमओसी ने दोहरी ओलंपिक पदक विजेता मनु के इटली के लुका में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उन्हें 13 से 22 मई तक ट्रेनिंग की स्वीकृति मिली है। इस 24 वर्षीय खिलाड़ी के साथ उनके कोच जसपाल राणा और फिजियोथेरेपिस्ट स्नेहिल खुराना जाएंगे।

मुन एशियाई खेलों में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल स्पधाओं में हिस्सा लेंगी और पदक की प्रबल दावेदार हैं। एमओसी ने लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह के उनके कोच के साथ अमेरिका में 15 मई से 17 जून तक 34 दिवसीय ट्रेनिंग और प्रतियोगिता दौरे के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता और एशियाई चैंपियनशिप में 5000 और 10,000 मीटर के स्वर्ण पदक विजेता गुलवीर लॉस एंजिलिस और नाशविले में स्पधाओं में हिस्सा लेंगे।

CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.
VCB PANEL, CRP,
TRANSFORMER, RMU ETC

SECURE METERS LTD.
ENERGY METER
(POSTPAID/PREPAID/
SOLAR/ABT)

SECURE

MITSUBISHI ELECTRIC
MCB/MCCB/ACB/
CONTRACTOR/DB

MITSUBISHI
ELECTRIC

Kumar Enterprises

GF-150 | DURGA TOWER | RDC | RAJ NAGAR | GHAZIABAD (UP) - 201001
TEL. : 0120-4137613 | EMAIL : ke.ghaziabad@gmail.com
SANJEEV KUMAR 9268566079

SHANTI NATH MANUFACTURERS

A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)

Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com

Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी सशक्तिकरण

सहायता के लिए संकल्पवान संवेदनशील नागरिक की पहचान

हां, मैं
संवेदनशील हूं

मुश्किल परिस्थिति में फंसे बच्चे की मदद करना
हम सभी का सामाजिक दायित्व है

जरुरतमंद बच्चों को सुरक्षित पारिवारिक वातावरण प्रदान करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित हैं

- **उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON)**
- **पालक देखरेख (FOSTER CARE)**
- **उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY)**
- **समूह पालक देखरेख (GROUP FOSTER CARE)**

आगे आएं और इस सामाजिक पहल का हिस्सा बनें

पात्रता

ऐसे व्यक्ति/संस्थाएं, जो बच्चों को आवश्यक देखरेख एवं बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम हों तथा किसी भी आपराधिक/अनैतिक गतिविधि में संलिप्त न हों, आवेदन कर सकते हैं

आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रारूप के लिए **विभागीय वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in** देखें
अथवा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क कर आवेदन करें

सुरक्षित परिवार - हर बच्चे का अधिकार
आपकी पहल किसी बच्चे का भविष्य बदल सकती है

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश @upwcd @upmahilakalyan upmahilakalyan upmahilakalyan

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP